RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

01-15 नवम्बर, 2018

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 8/ पृष्ठः 16
मूल्यः ₹ 25/-

www.therievtimes.com जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, उसकी बदनामी शुरु की जाती है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

जालसाजी एवं धोखाधड़ी

- सरकारी स्कूल में कार्यरत अपनी पत्नी के नाम पर निकलवाता रहा मिशन से वेतन
- सदस्यता के नाम पर लोगों से कैश लेकर नहीं दिया हिसाब
- कार्यालय से दस्तावेजों को किया चोरी
- नौकरी का झांसा देकर युवकों से कैश लेकर नहीं लिया संज्ञान

कम्पनी का कर्मचारी होकर कम्पनी को लगाता रहा चूना

वित्तिय अनियमित्ताओ को लेकर विनय हेटा पर एफ आई आर

खुद को छात्र संगठन का नेता बताने वाला विनय हेटा आखिरकार उसी कंपनी को गुमराह कर अपनी जेब भरता रहा जिसने उसे रोजगार दिया और एक सम्मानजनक ओहदा भी प्रदान किया। हैरानी इस बात की है कि विनय ने इस काम को अंजाम देने के लिए किसी और का नहीं बल्कि अपनी पत्नी के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। इसी बैंक अकांऊट को आधार बनाकर विनय हेटा ने फर्जी पंचायत फेसिलिटेटर के नाम पर आईआईआरडी से तीन बार पैसे खाते में ट्रांसफर करवाए।

दरअसल विनय हेटा जब आईआईआरडी में तैनात था तो वह अपनी पत्नी के नाम पर आईआईआरडी के खाते से पैसे ट्रांसफर करवाता रहा। जबकि वह आईआईआरडी की कर्मचारी थी ही नहीं। हेटा ने धोखे से अपनी पत्नी को कंपनी में पंचायत फेसिलिटेटर बताया क्योंकि बतौर जिला समन्वयक उन्हें पंचायत फेसिलिटेटर नियुक्त करने के लिए कंपनी की ओर से अधिकृत किया गया था। लेकिन हेटा ने अपनी पत्नी, जो एक सरकारी महकमें से जुड़ी हुई है, उसी को पंचायत फेसिलिटेटर बताया और एक नहीं बल्कि तीन बार कंपनी के खाते से उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कंपनी अपना इंटरनल ऑडिट कर रही थी। इस बारे में जब विनय हेटा से कंपनी ने जवाब तलब किया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद कंपनी की ओर से हेटा के खिलाफ जांच बिठाई गई और जांच में पता चला कि हेटा किस तरह जानबूझकर वित्तिय अनियमितताओं को अंजाम देता रहा। आईआईआरडी पिछले 14 सालों से जनकल्याण से जुड़े कार्य कर रही है।

- कंपनी ने किया 50 लाख का मानहानि का दावा
- मिशन की ब्लैक लिस्ट सूचि में नाम दर्ज
- सदस्य बनने की परिवार की वैधता हमेशा के लिए समाप्त
- पति-पत्नी को जालसाजी का नोटिस
- ढली थाना में 420, 460, धाराओं में एफ.आई.आर. पंजीकृत

हिमाचल के गांवों में लोगों को उनके घरों तक विभिन्न प्रकार की सुविधा पहुंचाने के लिए लिए वर्ष 2017 में मिशन रीव की शुरूआत की गई थी। इस दौरान विभिन्न युवाओं को इस मिशन रीव से जोड़कर जहां रोजगार का मौका दिया गया वहीं विभिन्न तरह की सुविधाएं भी लोगों तक पहुंचाई गई। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ लोग निजी

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
Police Station Dhalli, Shimla

स्वार्थों को साधने के लिए आईआईआरडी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विनय हेटा ने एक छात्र संगठन के बैनर तले आईआईआरडी पर कई निराधार आरोप लगाए हैं जो तथ्यों से बिल्कुल परे है। विनय हेटा जो 14 अक्तूबर 2017 से 29 अक्तूबर 2018 तक आईआईआरडी में कार्य कर रहा था उसके खिलाफ आईआईआरडी में रहते हुए कई वित्तीय मामलों में गड़बड़ी करने की जांच चल रही थी। जिसके आधार पर उसे कंपनी से निष्काषित कर दिया गया और उसे इस

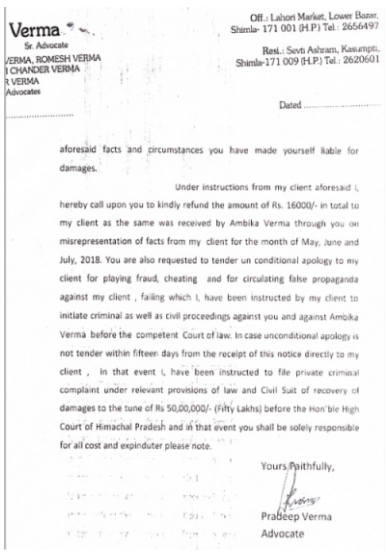
Verma
Sr. Advocate
Off.: Lahori Market, Lower Bazar, Shimla- 171 001 (H.P.) Tel.: 2656497
Res.: Sevti Ashram, Kasumpti, Shimla-171 009 (H.P.) Tel.: 2620601
Dated .....
aforesaid facts and circumstances you have made yourself liable for damages.
Under instructions from my client aforesaid I, hereby call upon you to kindly refund the amount of Rs. 16000/- in total to my client as the same was received by Ambika Verma through you on misrepresentation of facts from my client for the month of May, June and July, 2018. You are also requested to tender un conditional apology to my client for playing fraud, cheating and for circulating false propaganda against my client, failing which I, have been instructed by my client to initiate criminal as well as civil proceedings against you and against Ambika Verma before the competent Court of law. In case unconditional apology is not tender within fifteen days from the receipt of this notice directly to my client, In that event I, have been instructed to file private criminal complaint under relevant provisions of law and Civil Suit of recovery of damages to the tune of Rs 50,00,000/- (Fifty Lakhs) before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh and in that event you shall be solely responsible for all cost and expinduter please note.
Yours faithfully,
Pradeep Verma
Advocate

मामले में 29 अक्तूबर 2018 को लीगल नोटिस भी आईआईआरडी की ओर से जारी किया गया। इसी के बाद उसने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी की छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और फिर 4 नवंबर 2018 को मीडिया के सामने कंपनी से संबंधित तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया। हेटा ने मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कहा कि 6 हजार ऑफर लैटर जारी किए गए हैं जो उसके पास मौजूद हैं जबकि यह कार्यालय का गोपनीय रिकार्ड है। ऐसे में यह सारे दस्तोवेज चोरी करके उक्त व्यक्ति ने अपने पास रखते हुए कंपनी के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की है। इसी के चलते विनय हेटा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही डेफेमेशन एक्ट के तहत 50 लाख का डेफेमेशन भी फाइल किया गया है। विनय हेटा जब आईआईआरडी में तैनात थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर कुछ वित्तीय अनियमितताएं बरती। इसके अलावा उन्होंने कंपनी के निर्देशों का भी सही से पालन नहीं किया। इसी आधार पर उन पर कंपनी की ओर से जांच चल रही है और अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है क्योंकि आरोप लगाने वाले पर कंपनी ने पहले से जांच बैठा रखी थी। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। ताकि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटाई जा सके।

पूरे प्रकरण पर क्या कहते है प्रदेश भर मे मिशन रीव से जुड़े युवा

राकेश शर्मा, जिला समन्वयक चंबा, मिशन रीव

" मिशन रीव के बारे में कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे है की आईआईआरडी कंपनी ने करोड़ो का घोटाला किया है लेकिन हम चम्बा के कार्यरत आईआईआरडी के सभी कर्मचारी इस विषय में बताना चाहेंगे कि यह बात बिल्कुल निराधार है। जिला चम्बा में पिछले एक सालो में इसके साथ जो भी जुड़ा है उसको कंपनी के तरफ से पूरा सहयोग मिला है कंपनी में ज्वाइन करते ही हमें यह स्पस्ट कर दिया गया था की मिशन रीव एक सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम है जिसमें आपको सभी के सहयोग से इसे पूरा करना है और लोगो को उनके घर पर वह सेवाएं प्रदान करनी है जिसके लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तथा अन्य सेवाओं के लिए घर से बाहर मीलों का सफर तय करना पड़ता था। इससे लोगो को समय और धन काफी खर्च हो जाता था।"

मीनाक्षी, एडीसी बिलासपुर, मिशन रीव

" मिशन रीव के बारे में विगत कुछ दिन से कुछ तथाकथित लोगों द्वारा झूठी और मनगढंत खबरें फैलाई जा रही है । ये खबरें कुछ पूर्व में रीव के कर्मचारियों द्वारा फैलाई जा रही है जो कि बिना कुछ कार्य किए घर बैठे तनख़्वाह चाहते हैं । मैं विगत एक वर्ष से मिशन रीव के साथ अपनी सेवाऐं दे रही हूं। मुझे ब्लॉक कॉर्डिनेटर भर्ती होने का अवसर प्राप्त हुआ था और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बाद मुझे अतिरिक्त ज़िला समन्वयक बिलासपुर पदोन्नति मिली। अब हमारा लक्ष्य मिशन रीव को गांव–गांव तक ले जाने तथा इसे ऊंचाईयों तक पहुंचाने का है ताकि लोगों की सेवा का अवसर मिलता रहे और ये लोग जो घर बैठे मुफ़्त में तनख़्वाह चाहते हैं और मिशन रीव को अकारण ही अपमानित करते है, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने यह सब ग़लत किया है ।"

अंकुश नगरैक, एडीसी, शिमला, मिशन रीव

" मैंने मिशन रीव में ब्लॉक कोऑडिनेटर के तौर पर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं लगातार मिशन के साथ काम कर रहा हूं और शुरूआती नियमों के मुताबिक जैसे सेवाओं के बदले भुगतान की बात कही गई थी वह समय पर पूरी हो रही है। हमें समय पर सेवाओं के बदले भुगतान किया जा रहा है और हम इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट है। मेरे कार्य के आधार पर मुझे अब सहायक जिला समन्वयक बना दिया गया है। मिशन रीव के तहत गांवों में विभिन्न तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें स्वास्थ्य, कृषि , पशुधन और अन्य सेवाएं शामिल है। मेरे साथ जो सहयोगी बतौर पीएफ काम कर रहे हैं वह भी मिशन रीव को लेकर काफी उत्साहित है। वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा मिशन रीव को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है जिससे हमारे रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है।"

हनीश शर्मा, जिला समन्वयक, ऊना, मिशन रीव

" जैसा की आईआईआरडी के बारे में कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे है कि इस कंपनी द्वारा नियमित भुगतान नहीं किया है लेकिन हम ऊना में कार्यरत आईआईआरडी के सभी कर्मचारी इन अफवाहों का पूरी तरह खंडन करते हैं। ऊना में कार्य कर रहे मिशन रीव के सभी सदस्यों को उनके काम के अनुसार तय मानदेय दिया जा रहा है। जिला ऊना में मिशन अन्य एजेंसिओं से मिल कर लोगो के पेन कार्ड , आधार कार्ड और कई लोगो की जॉब एप्लीकेशन भरने जैसी सुविधा प्रदान की।"

विशाल नेगी, जिला समन्वयक किन्नौर, मिशन रीव

" किन्नौर में मिशन रीव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। किन्नौर में लोगों के घर तक सेवाएं और रोजमर्रा का सामान पहुंचाना आसान काम नहीं है। लेकिन मिशन रीव के तहत लोगों को यह सुविधाएं किन्नौर और लाहुल स्पीति के दूरदराज के गांवों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे कई उदाहरण है। इस काम को करने के लिए मिशन रीव के तहत जिला प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है उन्हें उचित मानदेय दिया जा रहा है।"

शैलेजा, सहायक ब्लॉक समन्वयक, कुल्लु मिशन रीव

" मिशन रीव ने प्रदेश भर में लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं और जो लोग अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं उन्हें समय पर वेतनमान भी मिल रहा है । मिशन रीव को बदनाम करने वाले लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं तथा उन्हें सार्वजनिक रुप से अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए ।"

ए डी सी, जितेन्द्र राणा सिरमौर , मिशन रीव

" मिशन रीव ने हिमाचल में युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर खोले हैं तथा हम स्वयं भी मिशन की सेवाओं को बतौर इसके कर्मचारी सिरमौर में गांव–गांव में जाकर दे रहे हैं। जिसने कार्य किया है उसे समय पर वेतनमान भी मिल रह है तथा जो लोग काम नहीं करना चाहते वो मुफ़्त में ही सुविधाऐं और पैसा चाहते हैं । ऐसे लोग अकारण ही मिशन को बदनाम करने में लगे हैं । हम सभी मिशन रीव के साथ है।"

शशी पाल, मिशन रीव

" मुझे मिशन रीव से जुड़े हुए करीब एक साल होने को है। मैं गांव रपोह मिसरा तह. अम्ब का रहने वाला हूं मुझे खुशी है कि मुझे अपने गांव में रोजगार मिला । इसके बदले में आईआईआरडी की ओर से तय मानकों के आधार पर मानदेय दिया जा रहा है।"

बलदेव पीएफ पंचायत खड़जौता, मिशन रीव

"मुझे पिछले एक साल से अपनी ही पंचायत में लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आईआईआरडी के मिशन रीव की ओर से समय–समय पर उचित मानदेय भी दिया जा रहा है।"

नितेश ठाकुर, एबीसी ब्लॉक चंबा, मिशन रीव

"आईआईआरडी के बारे में आ रही भ्रामक समाचारों के बारे बताना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है। हमारे काम के बदले हमें निरंतर वेतन दिया जा रहा है ,और मेरे साथ अभी भी 12 से 14 पंचायत फेसीलिटेटर काम कर रहे है और उन्हें भी तय नियमों के मुताबिक मानदेय समय पर मिल रहा है ।"

शेष पेज 7 पर

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
Institute for Integrated Rural Development

अपने उत्सवों को मनाऐं मिशन रीव के साथ अब मिठाई नहीं, रीव जैविक खाद और सदस्यता करवाकर दोस्तों को करें गिफ्ट

चिंतामुक्त जीवन से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी तक

हर कदम पर आपके जीवन के लिए मिशन रीव की योजनाओं को जोड़कर साथ मनाऐं त्यौहार

भारत के खेत ही हमारे धनकोष : रीव जैविक खाद से मिट्टी होगी गुलजार और स्वयं तथा समाज का भी होगा पोषण

मिशन रीव समस्त प्रदेशवासियों को त्यौहारो के अवसर पर दे रहा है सुनहरा अवसर। समस्त किसान रीव जैविक खाद का उपयोग कर अपने खेतों से ले सकते हैं कई गुणा अधिक एवं गुणवत्ताधारित पैदावार। साथ ही अपने खेतों की मिट्टी की जांच अब घर पर ही करवाऐं तथा उसी के हिसाब से अपने खेतों में रीव जैविक खाद एवं फसलों का चयन कर अपने जीवन को दें आर्थिक मज़बूती ।

रीव जैविक खाद :

- मिशन रीव के सहयोग से किसान स्वयं ही करते हैं खाद निर्माण
- मिट्टी की जांच के आधर पर रीव खाद में आवश्यक तत्वों का होता है संमिश्रण जिससे खाद आपके खेत के अनुसार की जाती है तैयार। एलगे (पावर बूस्टर) से होती है गुणवत्ता में बढ़ौतरी
- पूरे प्रदेश में बढ़ रही है रीव जैविक खाद की मांग । उपयोग के बाद परिणामों पर किसानों ने भी जताई प्रसन्नता ।

मृदा जांच :

- मंहगी और उपलब्धता की जटिलताओं को अब मिशन रीव ने किया सरल, छोटी एवं गांव–गांव तक सरलता से मृदा जांच मशीने उपलब्ध करवाई गई हैं ।
- खेत के हर कोने से मिट्टी की जांच कर उसी समय उसका परिणाम लोगों को घर पर ही दिया जा रहा है। इससे खेतों में वांछित फसलों को उगाने तथा उचित रीव खाद का उपयोग कर खेतों से सोना उगाने में किसान होंगे कामयाब ।

इसके अतिरिक्त आपके जीवन को धन और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आपकी सेवा की सुनिश्चितता के लिए मिशन रीव के दस प्रभाग आपके आवश्यकता आकलन के लिए हैं तैयार :

स्वास्थ्य डिविजन

- स्वास्थ्य स्लेट–12 विभिन्न टेस्टों के साथ प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच
- मोबाईल मेडीकल लैब–78 मानकों पर आधारित स्वास्थ्य जांच
- जनऔषधी केंद्र– लोगों को घर द्वार पर सस्ती दवा उपलब्ध कराना
- टेलीमेडीसन– लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा

कृषि डिविजन

- मृदा परीक्षण लैब– सदस्यों और किसानों के लिए सेवाऐं
- जैविक खाद निर्माण–किसानों को जैविक खाद निशुल्क प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित खाद को बाजार उपलब्ध कराना
- बीज और कृषि उपकरण–किसानों को उनकी मांग के आधार पर उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक उपकरण
- फीड सप्लीमेंट– पशुओं में दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य सुधार के लिए
- जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि विकास के लिए योजना बनाकर किसानों को सहयोग देना

यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन

- सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
- पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना
- बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटीलिटी सेवाऐं उपलब्ध कराना
- ई– स्टेंप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य ऑनलाइन सेवाऐं

उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन

- क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग
- प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में सेवाऐं
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग
- व्यवसाय शुरु करने से लेकर एक साल तक विभिन्न चरणों में सहयोग
- पहले से स्थापित व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग

बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन

- बचत, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहयोग
- बैंक लोन देना और रिकवरी व देनदारी संबंधि सेवाऐं
- संपत्ति प्रबंधन,जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पशुधन और फसल बीमा संबंधि सेवाऐं

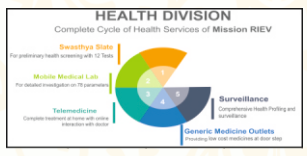

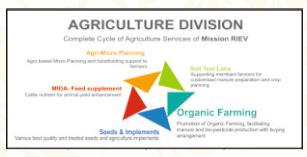

शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और अन्य विषयों पर ऑनलाइन कोचिंग
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर परीक्षण
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था व व्यस्क आयुवर्ग आधार पर काउंसलिंग
- ई–लर्निंग टूल्ज और अन्य तकनीक

सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा डिविजन

- बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाऐं
- पेंशन व उपलब्ध समय के सदुपयोग में सहयोग
- किसी भी आपदा और आकस्मिक दुर्घटना के समय सेवाऐं
- सामाजिक समस्या, कुरितियों और बुराईयों के निराकरण में पहल

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन

- गांवों में तैयार होने वाले शुद्ध उत्पादों का क्रय– विक्रय
- खरीददारों तक ग्रामीण उत्पादों को पहुंचाना
- गांवों में मांग आधारित उत्पादों की आपूर्ति करना और गांवों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना
- प्रदेश के भीतर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना

संपत्ति प्रबंधन डिविजन

- संपत्ति संबंधि देनदारियों, पंजीकरण, इंतकाल, राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाऐं
- नक्शा तैयार करवाने और स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी आदि में सहयोग करना
- विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने में सहयोग

मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन

- द रीव टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल
- ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना
- मिशन रीव ने इस सेवाओं को सार्वजनिक कर आम आदमी को उसकी परेशानियों से मुक्त करने और देश हित तथा स्वयं के विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समय प्रदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया है ।

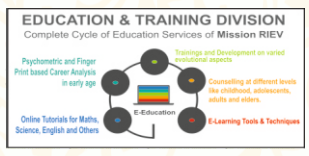

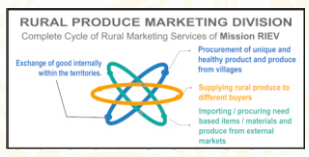

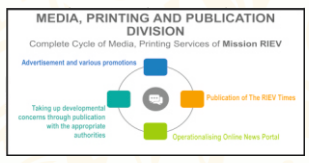

उपरोक्त सेवाओं को लाभ सदस्यता के उपरांत आवश्यकता आकलन के आधार पर लिया जा सकेगा और आपके जीवन को सरल व खुशहाल बनाने के लिए मिशन रीव है निरंतर तत्पर।

दिल से सेवा दिल से भुगतान

- आवश्यकता आकलन के साथ ही आपके द्वारा स्वीकार्य सेवाओं एवं आवश्यकताओं का रीव को ऑर्डिनेटर दिल से करेगा निदान और इसके लिए आप भी न्यूनतम निर्धारित भुगतान के बाद दिल से ही करेंगे भुगतान।
- सदस्यता के तीन प्रारुपों में अब आप के सामने है विकल्प : आजीवन सदस्यता, पूर्ववत वार्षिक सदस्यता तथा स्वैच्छिक सदस्यता
- सदस्यों का आवश्यकता आकलन कर , दस प्रभागों में स्वीकृत की गई सेवाओं को घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवाया जाऐगा तथा जो सेवाऐं सरकार, प्रशासन अथवा अन्य माध्यमों से उपलब्ध होनी है उनको उपयुक्त स्थान और समय पर हस्तांतरित किया जाऐगा।
- आओ त्यौहारों पर शतायु और निरोगी जीवन के साथ-साथ एक सामाजिक सुरक्षा एवं धन-वैभव जीवन की परिकल्पना को मिशन रीव के साथ जुड़कर करें साकार। इन त्यौहारों पर रीव के उत्पादों, सेवाओं और मिशन को आगे ले जाने के लिए हम सभी बने समाज के संवाहक।

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई है।
इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभाष नंबरों पर
संपर्क करें .... 9459584566 और 8219175636
साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम.... रीव जैविक खाद

इस बार त्यौहारों पर उपहारों के स्थान पर अपने सगे संबन्धियों को रीव जैविक खाद करें भेंट ताकि खेतों से निकले सोना, आपके गमलों में महके सुंदर पुष्प

रीव जैविक खाद अब 5,20,40 किलो की पैकिंग में भी उपलब्ध है

खाद में पोषक तत्वों की मात्रा

Parameter	Percentage
PH	7-8
Organic carbon	7.36 - 9
Nitrogen	1.69 - 2
Phosphorus	0.75 - 1
Potassium	1.17 - 1.50
Sulphur	0.042 - 0.70
Zinc	0.0053 - 0.0075
Iron	0.14 - 0.30
Copper	0.0011
Calcium	2.2 - 3
Magnesium	1.03 - 1.20
Boron	0.0012
Manganese	0.0097
Calorific Value	219.96

IIRD Complex, Bypass Road, Shanam, Sanjauli, Shimla, Himachal Pradesh-171006
Phone No. : 0177 2640761, Fax : 0177 2843528, Email : info@missionriev.in, Web : www.missionriev.in

नोट : कुछ लोग मिशन को ग़लत तरीके से प्रस्तुत करने और जनसमुदाय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे हरसंभव सावधान रहें.... मिशन रीव की सेवाओं को स्वयं समझे, जांचे व परखें, व उपरोक्त नम्बरो पर सम्पर्क करें।

RURALIZING INDIA-EMPOWERING VILLAGE RIEV

कि दुनिया देखती रह जाए

मिशन रीव की सेवाओं को सराहा

खण्ड विकास नारकंडा के अंतर्गत पंचायत जंजेली में लगा जागरुकता शिविर

टीम रीव, शिमला

दिल से सेवा दिल से भुगतान के महावाक्य के साथ मिशन रीव अब गांव–गांव में अपनी सेवाओं के साथ लोगों के साथ संपर्क साध रहा है । इसी के तहत शिमला ज़िले के ब्लॉक नारकंडा की जंजेली पंचायत में ग्रामीणों के साथ एक जागरुकता बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा गांव के बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया । बैठक में आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा तथा मिशन हैड प्रमुख सुषमा शर्मा ने भाग लिया । प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने लोगों से बात कर मिशन रीव की सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने कहा कि मिशन रीव की प्राथमिकता ग्रामीणजन हैं और उनकी सेवा ही इस मिशन का ध्येय है । इसके लिए अब तक की सबसे अनूठी पहल की गई है जिसके अंतर्गत समस्त सेवाओं को 10 प्रभागों में वितरित कर सभी समस्याओं को आवश्यकता आकलन के अंतर्गत लाया गया है। इसी आधार पर आपकी समस्त समस्याओं को रीव में समाधान तक लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । उन्होंने विस्तार से लोगों से उनकी समस्याओं एवं रोजगार को लेकर बातचीत की जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर बताया ।

कोहबाग में नशामुक्त हिमाचल की गूंज

एनएसएस शिविर के अभियान में 6 से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों ने लिया भाग

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

नशामुक्त हिमाचल अभियान के प्रथम चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में आईआईआरडी दूसरे चरण में प्रदेश के युवाओं एवं विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ परामर्शदाता की भूमिका में है। इसी के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहबाग में संस्था ने नशामुक्त हिमाचल अभियान 'ज़िंदगी जियें–नशा नहीं' का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के आयोजन के अंतर्गत किया गया। इस अवसर पर एनएसएस के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के अलावा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को जागरुक किया गया तथा उनसे चर्चा की गई।

आईआईआरडी की ओर से हेम राज चौहान एवं नरेन्द्र ठाकुर ने भाग लिया।

जैसी विभत्स स्थिति में होने से बचाना होगा। इससे पूर्व विद्यालय प्रधानाचार्य राजेन्द्र चौहान ने संस्था के पदाधिकारियों का स्वागत् किया और कहा कि कोहबाग में इस अभियान के प्रथम चरण पर भी बेहतरीन कार्य किया गया था। और अब द्वितीय चरण के लिए बच्चों के मध्य इस प्रकार की जागरुकता एवं प्रभावितों की पहचान की उन्हें सही मार्ग पर लाने हेतु प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आईआईआरडी का ये प्रयास बच्चों एवं युवाओं को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरुक कर एक मजबूत समाज एवं राष्ट्र की नींव रखेगा।

स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरिदास गर्ग ने इस अभियान पर संस्था के प्रयासों की तारीफ की और सभी बच्चों तथा अभिभावकों से अनुरोध किया कि नशे को न कहने से ही एक सशक्त समाज की स्थापना हो पाऐगी

हेम राज चौहान ने इस अवसर पर सर्वप्रथम संस्था के प्रथम चरण के अभियान की सफलता एवं उसके विश्लेषण पर चर्चा की। उन्होंने संस्था की ओर से द्वितीय चरण में प्रदान की जाने वाली सेवाओं और हिमाचल में होने वाले कार्यक्रमों पर भी बात रखी।

इस अवसर पर संस्था की ओर से नरेन्द्र ठाकुर ने अपने संबोधन में बताया कि नशे के दलदल से हिमाचल को पंजाब और हरियाणा और इसके लिए आईआईआरडी के प्रयास सदैव प्रशंसनीय रहेंगे। उन्होंने संस्था की ओर से आए प्रतिनिधियों का औपचारिक धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा किए और इस बात को स्वीकार किया कि एक एक–दूसरे की संगत में ग़लत रास्ता पकड़ लेते हैं। इसके लिए उन्हें कैसे इस नशे की गिरफ़्त से बाहर आना है, इस पर परामर्श की बात भी की।

रीव पहुंचा रहा दूर-दराज तक स्वास्थ्य सेवाऐं

स्पिति में आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जन सेवाओं के साथ तत्पर है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में भिन्न–भिन्न सेवाओं को लोगों के बीच टीम के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह रीव की टीम ने विशाल नेगी की अगुवाई में दूर दराज स्पिति में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया। जिसमें स्वास्थ्य संबन्धि जानकारी दी गई। विशाल नेगी ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता की बहुत

आवश्यकता है।

लोग स्वास्थ्य सेवाऐं लेने के लिए दूर तक जाने में आना–कानी करते हैं तथा इससे कई बार छोटी–छोटी बीमारियां गंभीर रुप ले लेती है। इसके लिए मिशन रीव आधारभूत स्वास्थ्य चेकअप और जानकारी लोगों को गांव में घर पर ही उपलब्ध करवाता है। इस शिविर में 50 लोगों ने भाग लिया तथा जानकारी भी प्राप्त की।

मिशन रीव किन्नौर और लाहौल स्पिति में हैंडलूम को लेकर सर्वेक्षण कर घर–घर जाकर लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे इस व्यवसाय में लगे लोगों की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर उन्हें अन्य सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा ।

स्वयं सहायता समूहों के साथ होगी उत्पादों की बिक्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मिशन रीव के अंतर्गत प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के साथ उत्पादों को बेचा और विज्ञापित किया जाएगा ताकि बाज़ार से सस्ते दामों पर गुणवत्ता वाले उत्पाद लोगों को सहज उपलब्ध करवाए जा सकें। इसकी शुरुआत शिमला से की गई है तथा इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मिशन रीव द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक वर्ग के लिए उत्पादों को बाज़ार मे उतारा गया है जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा किसानों के लिए रीव जैविक खाद भी शामिल है । ग्रामीण क्षेत्रों में रीव उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है तथा इसके लिए प्रत्येक वर्ग को मिशन रीव लाभान्वित करने के प्रयास कर रहा है ।

शिमला में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के साथ मिशन रीव प्रमुख सुषमा शर्मा ने बैठक कर मिशन रीव की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार के अवसरों पर भी जानकरी दी। ज़रुरतमंद महिलाओं के लिए मिशन रीव अपना व्यवसाय आरम्भ करने तथा इसके लिए उत्पादों को उचित स्थान एवं समय पर पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा। महिलाऐं अपना छोटा–मोटा कारोबार शुरु कर स्वावलंबी बनने की राह का चयन अब मिशन रीव से जुड़कर कर सकती है।

महिलाओं को मिशन रीव की दी जानकारी

उत्पादों से भी करवाया अवगत

द रीव टाइम्स ब्यूरो शिमला के संजौली में चल रहे प्रशिक्षण केन्द्र में 100 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को मिशन रीव की सेवाओं की समस्त जानकारी प्रदान की गई। मिशन रीव प्रमुख सुषमा शर्मा ने महिलाओं के साथ अलग–अलग सत्र में मिशन रीव की जनसेवाओं एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा विस्तार से बताया कि किस प्रकार मिशन रीव ग्रामीण महिलाओं को विशेष रुप से लक्षित कर उनके जीवन को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है। रीव द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी मिशन प्रमुख ने प्रस्तुतिकरण किया उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए मिशन रीव के तहत बहुत से उत्पादों को सरलता से बाजार से सस्ते दामों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही किसानों के लिए मृदा जांच, रीव जैविक खाद आदि भी अब सरलता से उपलब्ध है।

मिशन प्रमुख सुषमा शर्मा ने दी सेवाओं की जानकारी

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर घर पर ही प्राप्त हो इसके लिए रीव महिलाओं को प्रशिक्षण देगा तथा उनके व्यवसाय को स्थापित करने में सहयोग भी देगा।

किन्नौर में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के दौरे के दौरान बहुत सौगातें ज़िले को मिली और लोगों ने मुख्यमंत्री का दिल खोल कर स्वागत भी किया । इसी के चलते मिशन रीव टीम किन्नौर ने भी किन्नौर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पधारने पर उनका स्वागत किया । किन्नौर में सेवारत दीपा, और विशाल नेगी ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका स्वागत किया तथा उन्हें अवगत करवाया ।

अध्यापकों की कमी : विद्यार्थियों को पड़ रही है भारी

खटनोल विद्यालय में नहीं है विभिन्न पदों पर अध्यापक

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खटनोल में विभिन्न पदों पर अध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। विद्यालय में वर्तमान में टीजीटी आर्टस, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी केमेस्ट्री एवं पीजीटी कंप्युटर विज्ञान के पदों पर कोई भी नियुक्ति नहीं है। परीक्षाओं का समय है तथा ऐसे में इतने महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त होने से कहीं न कहीं बच्चों के साथ अभिभावकों की चिंता का भी कारण है। द रीव टाईम्स ने इस विषय पर जब पड़ताल की तो बच्चों ने स्वीकार किया कि अध्यापकों न होने के कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं अभिभावकों ने भी शिकायत की कि सरकार इस विषय को लेकर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तथा तुरंत विद्यालय में उक्त अध्यापकों की नियुक्ति करें ताकि उनके बच्चें अपनी पढ़ाई को सुचारु रख सके। इस विषय पर मिशन रीव के प्रतिनिधि नरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि रीव इस मुद्दे को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से चर्चा कर समाधान करने के प्रयास कर रहा है तथा बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया जाएगा ।

सोलन से रीव जैविक खाद पहुंचेगी पूरे हिमाचल में

किसानों के सहयोग से तैयार हुई सैंकड़ों क्विंटल खाद

टीम रीव, सोलन

रीव जैविक खाद निर्माण में सोलन बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसी के तहत सोलन में किसानों ने मिशन रीव के साथ सैंकड़ों टन खाद निर्माण किया है। यह खाद अब पूरे प्रदेश में मांग के अनुसार वितरित की जा रही है। इसकी बुकिंग पहले ही की जा चुकी है क्योंकि लगभग सभी ज़िलों इसकी मांग है। खाद को 40 किलो की पैकिंग में पैक किया गया है।

इसके अलावा दीपावली के अवसर पर रीव

खाद के छोटे पैक गिफ्ट करने के उद्देश्य से 5 और बीस किलो के पैकट भी बनाए गए हैं। सोलन में किसानों को रीव खाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया था तथा उसके बाद गांव में किसानों ने अपने स्तर पर खाद तैयार की। खाद के दो प्रकार है। एक तो प्रथम चरण में रीव जैविक खाद जिसे सामान्य विधि से तैयार किया जाता है तथा दूसरी जिसमें एलगे पावर बूस्टर आदि मिला कर और अधिक गुणवत्ता बढ़ा दी जाती है।

दीवाली पर बढ़ी रीव जैविक खाद के छोटे पैकट की मांग

ऐसा इसलिए आवश्यकता रहती है क्योंकि रीव मृदा जांच में यदि मिट्टी के गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है तो एलगे मिश्रित रीव जैविक खाद का उपयोग किया जाता है।

सोलन से रीव प्रतिनिधि विजय कुमार ने बताया कि ज़िले में अधिक से अधिक खाद निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रीव सचिवालय से अजय कुमार ने भी बताया कि सोलन में किसान जागरुक होकर कार्य कर रहे हैं, खेतों में अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं।

FLYERS GROUP
PRIVATE LIMITED

	FGPL Rate*	Market Rate
LED HD Television 24"	8200.00	11200.00
LED HD Television 32"	11000.00	15000.00
LED HD Smart Television 32"	13500.00	16000.00
LED HD Television 40"	15000.00	19500.00
LED HD Smart Television 40"	18000.00	22000.00
LED HD Smart Television 50"	32900.00	42000.00

*Price Inclusive of GST + 1 Year Warranty

For queries & bulk order Contact : +91-94595 84566, +91-82191 75636
Flyers Group Private Limited, IIRD Complex, Byepass Road, Shanan
Shimla, Himachal Pradesh - 171006

ADVT

सोलन में स्वास्थ्य स्लेट से स्वास्थ्य देखभाल

टीम रीव, सोलन

मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट से लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके चलते गांव में लोगों को काफी राहत है क्योंकि लोगों को बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

स्वास्थ्य स्लेट से टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है। सोलन के 60 वर्षीय राजेन्द्र का कहना है कि अब उन्हें हर माह अस्पताल नहीं जाना पड़ता और उनका शुगर और बीपी का टेस्ट घर पर ही हो जाता है। इसे उन्होंने काफी राहत महसूस की है।

ऊना में दो सालों के भीतर करें क्षयरोग नियंत्रण

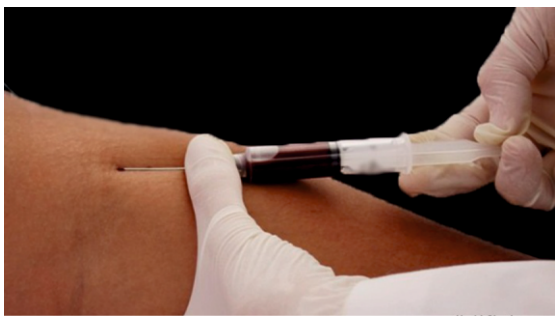

टीम रीव, ऊना

मुख्यमंत्री क्षयरोग निवारण योजना के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस का आयोजन जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल संगठन ऊना के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने की। कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार डॉ. रविंद्र, डॉ. अशोक भारद्वाज, डॉ. सतीश पुंडीर और टीवी सेनीटोरियम धर्मपुर सोलन की टीम ने टीबी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम में आए निजी अस्पतालों के एमबीबीएस, एमडी और एमएस को टीबी की जांच, उपचार और सूचना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष डॉ. एसके नंदा, जिला आईएमए अध्यक्ष डॉ. राकेश अग्निहोत्री और महासचिव डॉ. सुरिंद्र सिंह सूर्या और भूतपूर्व जिला क्षयरोग अधिकारी डॉ. आरएस डढवाल ने भी विचार रखें।

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने निजी चिकित्सकों को क्षय रोग की जांच और उपचार को लेकर एक मूवमेंट के तौर पर कार्य करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने जिला में 2020 तक क्षयरोग पर नियंत्रण करने का भी लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में मेडिकल स्टोरों पर टीबी की निजी दवाई पर पूर्ण रूप से प्रबंध करने का आह्वान किया है और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से क्षयरोग की दवाई का प्रावधान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने सभी निजी चिकित्सकों से प्रदेश में 2022 तक क्षयरोग नियंत्रण पर पाने के सहयोग की अपील की। इस अवसर पर जिला के लगभग 40 चिकित्सकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

शिलाई सीएचसी को सिविल अस्पताल का दर्जा

टीम रीव, सिरमौर

जिले शिलाई विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में 3.50 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शिलाई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिलाई को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोनहाट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। शिलाई क्षेत्र में पेयजल की कमी से निपटने के लिए क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर 26 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1.60 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिलाई में एक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिलाई में मुद्रिका बस आरंभ करने और शिलाई में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा भी सीएम ने मंच से की। इस मौके पर अगले वित्त वर्ष में रोनहाट कॉलेज भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की गई।

डिग्री कॉलेज शिलाई में शुरू होंगी पीजी कक्षाएं

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिलाई और कफोटा में दो नए ट्रेड आरंभ करने के साथ–साथ डिग्री कॉलेज शिलाई में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सतौन में एस्ट्रो–टर्फ के निर्माण के लिए 15 लाख रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिलाई में मिनी सचिवालय, राजस्व सदन के निर्माण के अतिरिक्त अशयाड़ में प्राथमिक पाठशाला खोली जाएंगी। शिलाई स्थित विश्राम गृह का विस्तार करने के अलावा यहां अतिरिक्त भवन का भी निर्माण किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी कार्यालय शिलाई के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

कांडो दुगाना पेयजल योजना का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने तिलगन खड्ड पर बने पुल, कांडो दुगाणा उठाऊ पेयजल योजना, जाखना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाखू भवन और राजकीय डिग्री कॉलेज के कर्मचारी आवासों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने शिलाई में अग्निशमन पोस्ट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का पांवटा साहिब से शिलाई जाते हुए सतौन और दुगाना में गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

सुबह आठ से शाम आठ बजे तक खुली रहेगी महिमा लाइब्रेरी

सिरमौर।

ऐतिहासिक महिमा लाइब्रेरी में विद्यार्थियों और पाठकों की सुविधा को देखते हुए समय सारिणी में बदलाव किया गया है। महिमा लाईब्रेरी अब प्रातरू 8 बजे से सांय 8 बजे तक खुली रहेगी। लाइब्रेरी में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के उपरांत समय सारिणी बदलाव करने निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही महिमा लाइब्रेरी को ई–लाईब्रेरी बनाना भी विचाराधीन है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हाल ही में महिमा लाइब्रेरी का दौरा किया और समय सारिणी में बदलाव के संदर्भ में विद्यार्थियों और पाठकों को यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में पाठकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से नाहन लाइब्रेरी को ई–लाइब्रेरी बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे। महिमा लाइब्रेरी में टैब के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है। लाइब्रेरी परिसर में अतिरिक्त स्थान एवं रीडिंग रूम को विकसित करने का भी प्रयास किया जाए

एनएच पर धंसने वाले पहाड़ों को बचाने के लिए काम शुरू

टीम रीव, सोलन

भारी बारिश के कारण कालका–शिमला हाईवे पर चक्कीमोड़, सनवारा, धर्मपुर में कई घरों को नुकसान पहुंचा था। अब हार्डिंग वार्ड से नीचे और हाईवे के साथ सटे पहाड़ को सुरक्षित करने के लिए फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी ने उच्च स्तरीय तकनीक का प्रयोग कर इसे रोकने का कार्य कर रही है। इसमें करोड़ों रुपये लगाए जा रहे हैं।

इसके प्रथम चरण में पहाड़ से कभी मिट्टी को निकाल कर उसके बाद पहाड़ में ड्राई मिक्स शॉटकंक्रीट किया जाएगा। दूसरे चरण में वायरमेश, जाली, कंक्रीट स्प्रे किया जाएगा। अंतिम चरण में पहाड़ के बीच एसडी रोक बोल्ट लगाए जाएंगे जो पहाड़ के अंदर आठ मीटर तक डाले जाएंगे। इससे पहाड़ अंदर से मजबूत बन जाएगा और इससे पहाड़ में दरारें सहित ढहने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा।

कंपनी के इंजीनियर राहुल, जसवीर व रमेश तोमर ने बताया कि पहाड़ को खिसकने से बचाने के लिए कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया है। इसमें इसकी मजबूती के लिए हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें 150 मीटर ऊंचे पहाड़ को रोकने किए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

घर पर ही मिल रहा जरूरत का सामान

टीम रीव, सिरमौर

मिशन रीव द्वारा लोगों को गांवों में ही उनके घर पर वह सामान पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए पहले उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करके बाजार जाना पड़ता था। विभिन्न सेवाओं के साथ ही अब लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी उनके अपने घर में ही मिशन रीव के तहत पहुंचाया जा रहा है।

लोगों की जरूरतों का आंकलन करने के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही घर पर जाकर भी उनकी जरूरतें पूछी जा रही है। इस दौरान मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में भी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। सिरमौर की दूरदराज की कई पंचायतों में में इस तरह के शिविरों का आयोजन करीब एक सप्ताह तक किया गया। इसके बाद लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया गया। इसमें क्रॉकरी, डिटर्जेंट, शैंपू समेत अन्य सामान लोगों को उनके घर पर ही उपलब्ध कराया गया।

मिशन रीव के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी–छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है। शिलाई निवासी अजय, रीता व अन्य लोगों का कहना है कि मिशन रीव के जरिए वह रोजमर्रा की जरूरत का सामान आसानी से प्राप्त कर पा रह हैं। इसके साथ ही पशुओं के लिए फीड सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराई गई।

जिले के स्कूल बनेंगे आदर्श

टीम रीव, ऊना

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि टीच ऊना कार्यक्रम के तहत जिले के चुनिंदा प्राथमिक स्कूलों को बतौर आदर्श विद्यालय विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में छह प्राथमिक शिक्षा खंड हैं। प्रत्येक शिक्षा खंड से कम से कम एक–एक स्कूल को टीच ऊना योजना के माध्यम से बतौर आदर्श विद्यालय विकसित किया जाएगा।

चयनित स्कूलों में बच्चों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में टीच ऊना के तहत आदर्श प्राथमिक स्कूलों के चयन के लिए आज से प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए ऊना के पास लाल सिंगी प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया गया। इस दौरान स्कूल में उपलब्ध मूलभूत ढांचे, खेल का मैदान, शौचालय आदि सुविधाओं के अलावा बच्चों की संख्या को भी देखा गया।

उन्होंने बताया कि जिला में जल्द ही ऐसे स्कूलों का चयन कर लिया जाएगा, जहां बच्चों को निजी स्कूलों की तरह तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बतौर आदर्श विद्यालय विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निजी स्कूलों की तर्ज पर तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाना है ताकि ग्रामीण बच्चे भी सुविधाओं के अभाव में पीछे न रहें।

अब गांव में आधा हो गया इलाज का खर्च

कांगड़ा में जनऔषधि केंद्रों से ग्रामीणों को मिल रही सुविधा

टीम रीव, कांगड़ा

जिला कांगड़ा में मिशन रीव के तहत खोले गए जनऔषधि केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इन केंद्रों की खास बात यह है कि यह केंद्र ऐसी जगहों पर खोले गए हैं जहां ग्रामीण आसानी से पहुंच सकते हैं। शहर जाकर मंहगी दवाईयां लेने का झंझट अब नहीं रहा और इलाज पर होने वाला खर्च भी पहले की अपेक्षा कहीं कम हो गया है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि जब से जनऔषधि केंद्रों से दवाईयां लेनी शुरू की तब से इलाज का खर्च आधा हो गया। जिला कांगड़ा में वर्तमान में कुल चार जनऔषधि केन्द्र खोले गए हैं। इनमें पालमपुर के बनूरी, पंचरूखी, नूरपुर और सादू बरगरां जनऔषधि केंद्र शामिल है। नूरपुर के स्थानीय निवासी विनोद ने कहा कि वह डाक्टर की सलाह पर नियमित रूप से दवाईयां खाते हैं। पहले उन्हें बाजार से दवाईयां लेनी पड़ती थी। लेकिन अब नूरपुर में ही जैनेरिक औषधि केंद्र खुलने से ब्लॉक में ही लोगों को सस्ती दवाईयां मिल रही है। 65 वर्षीय लीलावती का कहना है कि वह अक्सर अस्वस्थ्य रहती हैं और उन्हें नियमित तौर पर दवाईयां खानी पड़ती है। हाल ये है कि उन्हें आय का करीब 40 फीसदी अपने स्वास्थ्य की देखभाल पर ही खर्च करना पड़ता है।

कांगड़ा में खुले चार जनऔषधि केंद्र पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे 300 जनऔषधि केंद्र

लेकिन अब जैनेरिक केंद्र से दवाईयों खरीद रहे हैं तो दवाईयों पर होने वाला खर्च पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो गया है। लोगों का कहना है कि आईआईआरडी को इस तरह के जैनरिक स्टोर सभी गांवों में खोलने चाहिए ताकि गांव में सस्ती दवाईयां लोगों को मिल सके। गांव के लोगों को अक्सर साधारण दवाईयों के लिए भी कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है लेकिन अब जैनरिक स्टोर खुलने से आसानी से गांव में ही दवा मिलेगी।

अन्य जिलों में मिल रही सुविधा

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और हमीरपुर में जनऔषधि केन्द्र खुल चुके हैं और गांव के लोगों को इसका काफी लाभ मिल रहा है।

जनऔषधि केंद्रो पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी की दवाईयां उपलब्ध होगी। इससे पहले लोगों को सस्ती दवाओं के लिए शहरों में भटकना पड़ता था।

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि आईआईआरडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहा है।

विकासात्मक योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहा मिशन रीव

लोगों को दी जा रही जानकारी

टीम रीव, बिलासपुर

हिमाचल में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिश्न रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इसके लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी तरह बिलासपुर की पडयालग, दाबला, कासरू, बेरीराजदियां, हंबोट पंचायत में इसी तरह के शिविरों का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मंडल, स्वंय सहायता समूह और स्थानीय लोगों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

इस दौरान मिशन रीव की सेवाओं के साथ–साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। रीव प्रतिनिधि ने जब लोगों से पूछा की उन्हें सरकारी योजनाओं की कितनी जानकारी है, तो लोगों ने साफ कहा कि योजनाएं तो पता है लेकिन इनका लाभ कैसे और कहां से मिलेगा, इसके बारे में नहीं पता। इसी तरह कृषि संबंधि योजनाओं के बारे में भी लोगों ने मिशन रीव के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की।

इसके अतिरिक्त लोगों को मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराए जा रहे एनीमल फूड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान ग्रामीणों के घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया।

सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहा मिशन रीव रोजमर्रा का सामान भी पहुंच रहा है घर

इस दौरान लोगों ने पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की और मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद उन्हें सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके काफी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।

घर-घर जाकर हो रहा आवश्यकता आंकलन

गांव के लोगों की जरूरतें पहचान रहा मिशन रीव

टीम रीव, हमीरपुर

मिशन रीव के तहत समस्त सेवाओं की लोगों तक उपलब्धता ही मिशन का ध्येय है । सदस्यता ग्रहण करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य सदस्यों की आवश्यकताओं का आकलन करना है। इस आकलन के पीछे सदस्यों एवं उनके समस्त परिवारजनों की एक–एक व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं की पहचान करना एवं उनके समाधान के लिए प्रयास करना है।

इसके लिए मिशन प्रतिनिधियों की ओर से लोगों के घरों में जाकर उनकी आवश्यकतों का आंकलन किया जा रहा है। अभी तक जिला हमीरपुर में ही करीब एक हजार से अधिक लोगों की आवश्यकता का आंकलन उनके घर पर जाकर ही किया जा चुका है। इतना ही नहीं प्राथमिकता आधार पर लोगों की आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया भी जारी है।

सदस्यों की आवश्यकता आकलन के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में मिशन रीव के प्रतिनिधि लोगों की पूरी सहायता करते हैं। फार्म भरने से लेकर आकलन की पूरी प्रक्रिया मिशन प्रतिनिधि पूरी करते हैं।

आवश्यकता आकलन का भिन्न वर्गों में विभाजन आवश्यकता आकलन को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है । इन वर्गों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हर क्षेत्र से संबन्धित समस्या अथवा आवश्यकता इसमें शामिल की जा सके। इतना ही नहीं अलग से सुझाव देने के लिए भी विकल्प रखा गया है। जहां संयुक्त रूप से आवश्यकता आंकलन किया जाता है वहीं यदि कोई अलग से अपनी समस्या साझा करना चाहे तो उसकी भी पूरी सहायता रीव टीम की ओर से की जाती है।

इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियों से लोगों की आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। इसमें सभी की दैनिक एवं मूलभूत समस्याओं को शामिल किया गया है। किसान से संबन्धित प्रश्न किसान की समस्त समस्याओं को से जुड़े हैं तो वहीं विद्यार्थी अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के साथ ही प्रश्नावली तैयार की गई है।

आवश्यकता आकलन का आधार घर–द्वार की सेवाएं रीव के फेसिलिटेटर गांव में आवश्यकता आकलन को ही आधार बनाकर सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं। समस्या पंचायत स्तर की हो, खण्ड स्तर की हो, ज़िला अथवा सरकार के स्तर की हो, मिशन रीव के तहत हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है।

लोगों को दी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी

टीम रीव, हमीरपुर

रिवालसर में मिशन रीव के स्वास्थ्य सेवक की ओर से स्थानीय लोगों के घरों में जाकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्हें मिशन रीव के तहत उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सेवाओं की भी जानकारी दी जा रही है। हैल्थ टेस्टिंग मशीन स्वास्थ्य स्लेट के बारे में जानकारी दी। मिशन रीव स्वास्थ्य जांच के साथ साथ घर द्वार पर सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवा रहा है, इस बारे में भी लोगों को बताया गया।

स्वास्थ्य स्लेट से हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में लोगों के घरों में ही जाकर टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक तीन सौ से अधिक लोगों के स्वास्थ्स की जांच उनके घरों पर जाकर ही की जा चुकी है।

मिशन रीव की ओर से यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की ग्रामीण लोगों की ओर से प्रशंसा भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि घर पर ही टेस्ट सुविधा से स्वास्थ्य की देखभाल आसान हो गई है।

बाजार जाने का झंझट खत्म

घर पहुंच रहा जरूरत का सामान

टीम रीव, कांगड़ा

मिशन रीव के तहत लोगों को गांवों में ही उनके घर पर वह सामान पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए पहले उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करके बाजार जाना पड़ता था। लेकिन अब गांव में उनके अपने घर में ही मिशन रीव के तहत जरूरत का सारा सामान पहुंचाया जा रहा है।

लोगों के घरों पर जाकर मिशन रीव के प्रतिनिधि आवश्यकता आंकलन कर रहे हैं। इसके लिए अलग से आवश्यकता आकलन फॉर्म बनाए गए हैं। इसके माध्यम से लोगों की जरूरतों को जानकर उन्हें मिशन रीव की सेवाएं प्रदान की जा रही है।

लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया गया। स्वास्थ्य और कृषि संबंधि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रानिक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कॉकरी व अन्य सामान भी लोगों को उनके घरों पर बाजार से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

घर जाकर पूछ रहे मिशन प्रतिनिधि, कृषि और पशु पालन के बारे में

मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है।

भूस्खलन से दहशत में लोग

चार गांवों के अस्तित्व पर संकट

टीम रीव, कांगड़ा

प्रकृति से छेड़छाड़ अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन मानव जीवन के लिए ही संकट पैदा कर देता है। ऐसा ही उदाहरण कांगड़ा के चार गांवों में देखने को मिल रहा है।

उपमंडल कांगड़ा के चार गांवों को भू–सख्लन से खतरा पैदा हो गया है। इसके चलते भड़ियारा, वेद्दी, खडियारा और केटलू आदि गांवों के करीब 90 घरों को खतरा पैदा हो गया है। यह समस्या गज खड्ड में लगातार हो रहे खनन के कारण हो रही है। हालांकि, अब इस क्षेत्र में खनन पर रोक लग चुकी है लेकिन पहले हुए खनन का खामियाजा अब भी ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गज खड्ड के कभी भी रौद्र रूप धारण करने की स्थिति में पहाड़ी पर बसे गांवों को खतरा हो सकता है। संघर्ष समिति के प्रधान उधम सिंह डढवाल के एक प्रेस बयान के मुताबिक इसके बारे में कई बार स्थानीय विधायकों से लेकर मंत्रियों को अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक इस समस्या का हल नहीं हुआ। डढवाल ने कहा कि इसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत करवाया है। पीएम आफिस से मिले पत्र के अनुसार उन्होंने वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस संवेदनशील क्षेत्र की जांच कर उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर जिलाधीश को गंभीरता से विचार करने के लिए कहा है, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद आज दिन तक यहां पर हो रहे भू–स्खलन को रोकने के लिए कोई उचित योजना नहीं बनाई गई है।

खस्ताहाल सड़क बनी परेशानी का सबब

टीम रीव, हमीरपुर

उपमंडल बड़सर के अंतर्गत पड़ती बिझड़ी से उखली सड़क के विस्तारीकरण का कार्य जल्द पूरा न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से उड़ती धूल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कार्य को पूरा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। लेकिन, अभी तक कार्य अधर में लटका हुआ है। जानकारी के मुताबिक करोड़ों की लागत से होने वाला यह कार्य 17 नवंबर 2016 को शुरू हुआ। इसे 16 जून 2018 तक पूरा किया जाना जाना था लेकिन यह अभी भी अधर में है। इस सड़क पर अभी तक टायरिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। टायरिंग न होने से सड़क पर डाली मिट्टी और पत्थर उखड़ना शुरू हो गए हैं। सड़क पर बिखरी पड़ी बजरी के चलते दोपहिया वाहन चलाना काफी मुश्किल हो गया है। बल्ह बिहाल, धंगोटा और पैरवीं गांवों के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि सड़क के कार्य को दोबारा से शुरू करवाया जाए।

आयुष का स्मार्ट सिटी मॉडल सबसे बेहतरीन

चंबा में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन

टीम रीव, चंबा

शहर के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित राज्यस्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता तथा उपविजेताओं को सम्मानित किया। नन्हे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल में सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल शिमला के आयूष चौहान ने राज्यभर में पहला स्थान हासिल किया। आयूष ने ईको फ्रेंड्ली सोसायटी के तहत एक स्मार्ट सिटी का मॉडल बनाया था। इसमें सोलर एनर्जी पर फोकस किया गया। दूसरे नंबर पर ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल नगरोटा बगवां के मयंक भारद्वाज रहे। मयंक ने वर्टिकल फाइमंग का मॉडल बनाया। इसमें छत पर ही खेती करने पर ध्यान आकर्षित किया गया है। तीसरे स्थान पर कन्या विद्यालय चंबा की कृतिका शर्मा रही। कृतिका ने क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन पर मॉडल बनाया। इसमें अलग–अलग तरह का कूड़ा रखने का प्रबंध किया गया है। इससे गंदगी नहीं फैलगी। इसके अलावा जूनियर अर्बन विज्ञान प्रश्नोत्तरी में सोलन जिला के नव ज्योति सेंचूरी स्कूल खरूणी ने पहला, डीएवी पब्लिक स्कूल नाहन ने दूसरा और मिनर्वा पब्लिक स्कूल घुमारवीं ने तीसरा स्थान हासिल किया।

एचबी और बीपी की जांच

टीम रीव, चंबा

मिशन रीव के तहत गांवों में लोगों को घर पर ही प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में चंबा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भनोता, शिव मंदिर में स्वस्थ्य सेवक धर्मेंदर कुमार और सहायक जिला समन्वयक विकास कुमार की अगुवाई में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में पंचायत के 20 से अधिक लोगों के विभिन्न टेस्ट किए गए। इसमें शुगर, एचबी की जांच की गई।

इसके अलावा लोगों को मिशन रीव के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। जांच शिविर में जयवन्त शर्मा, शक्ति प्रशाद ,राजकुमार, दर्शन देवी, मधु देवी, रीनू देवी, हेम राज कपूर जोगिंदर सिंह मिंया, जितेंदर सिंह और जोनू ठाकुर व अन्य कई लोगों के टेस्ट किये गए। इन सभी लोगों ने मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही सेवाओं की सराहना की और कहा कि मिशन ने गांवों के लोगों का जीवन आसान बना दिया हैं।

चम्बा के सलूनी ब्लॉक की खडजुटा पंचायत में मिशन रीव की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में जांच करवाते लोग

सड़क सुविधा को तरस रहे सालवां के तीन गांव

टीम रीव, चंबा

विकास खंड सलूणी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सालवां के तीन गांवों में सड़क सुविधा न होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सालवां पंचायत के सलण, दिहोई और थलोगा गांवों की 1500 से अधिक की आबादी अभी भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा को तरस रही है। यहां के लोगों को जरुरत की खाद्य सामग्री और अन्य सामान पीठ या खच्चरों पर लाद कर घरों को ले जाना पड़ता है। यही नहीं उक्त गांवों में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसे पीठ और पालकी पर उठाकर सड़क तक ले जाना पड़ता है। इसके बाद गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी उनके गांव सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क न होने का सबसे बड़ा खामियाजा गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को उठाना पड़ाता है, उन्हें प्रसव पीड़ा के दौरान मुश्किल से सड़क तक ले जाया जाता है। उन्होंने कई बार विभाग से सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोनिवि के अधिषाशी अभियंता अरूण पठानिया ने बताया कि लोग अगर सड़क में आने वाली निजी भूमि विभाग के नाम करते हैं, तो इसके ऊपर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सहाली का हाल भी बदहाल

जनजातीय क्षेत्र पांगी की सहाली पंचायत के धनाला गांव का हाल भी अलग नहीं है। यहां भी लोग अरसे से सड़क सुविधा को तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक सड़क न होने के कारण स्कूली बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। इतना ही नहीं अगर गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो लोगों की सहायता से उसे पीठ या पालकी में उठाकर मुख्य सड़क सहाली जोरो प्वाइंट तक पहुंचाना पड़ता है। यहां से उसे एंबुलेंस या निजी वाहन से किलाड़ अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों ने सरकार और लोनिवि से मांग की कि गांव शीघ्र सड़क सुविधा से जोड़ा जाए।

मण्डी में 10 हजार किलो खाद तैयार

मिशन रीव ने ग्रामीणों को दिया प्रशिक्षण

टीम रीव, मण्डी

प्रदेश में पिछले काफी समय से जैविक खेती को लेकर योजनाएं बन रही है लेकिन अधिकतर किसानों को अभी जैविक खेती की पूरी जानकारी नहीं है। इस समस्या का समाधान करके प्रदेश को जैविक राज्य बनाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला (आईआईआरडी) मिशन रीव के तहत अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मिशन रीव के तहत प्रदेश के गांवों में किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है।

इतना ही नहीं किसानों को जैविक खाद बिक्री के लिए बाज़ार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिला शिमला में ही किसानों ने मिशन रीव के सहयोग से 20 हजार किलो जैविक खाद तैयार कर ली है और अब वह मिशन रीव के माध्यम से इसकी बिक्री करके आय प्राप्त करने की तैयारी में है।

खाद की बिक्री के लिए बाजार भी कराया उपलब्ध

यह पहली बार है कि कोई संस्था गांव के लोगों को उन्हीं के घरद्वार पर रोजगार के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत पंचायतों में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है। संस्था के ये प्रतिनिधि गांवों में ही किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन प्रतिनिधियों को आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है।

लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन मिशन रीव ने इसे आसान बना दिया है। आईआईआरडी के प्रबंधक निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि हिमाचल का विकास तभी संभव है जब गांव के लोगों के पास रोजगार और व्यवसाय के अवसर होंगे। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

कैसे बनती है जैविक खाद

आईआईआरडी ने एक ऐसे बैक्टिरिया का उपयोग किया जिसको गोबर अथवा अन्य अपशिष्ट पदार्थों मे मिलाकर जैविक खाद तैयार की जाती है। यह तकनीक National Centre for Organic Farming (NCOF) जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है, द्वारा सामने लाई गई है जिसे किसानों तक गांव में मिशन रीव पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

सबसे बड़ी इसमें विशेषता यह है कि यह प्रचलित अन्य किसी भी प्रकार की खादों में सबसे कम समय में तैयार होती है । साथ ही गुणवत्ता के मापदंडों पर भी यह औरों से आगे हैं । इसे लगभग 30 से 40 दिनों के बीच तैयार कर लिया जाता है । इसका एक मुख्य गुण यह है कि यह ज़मीन के अंदर जाकर मिट्टी के पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ा देता हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाता है ।

पांच सौ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांचा

टीम रीव, कुल्लू

अन्य जिलों की तरह ही कुल्लू में भी स्वास्थ्य स्लेट लोगों के स्वास्थ्य देखभाल में अहम साबित हो रही है। स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से लोगों के घरों पर ही उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद अगर कोई चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहते हैं तो वह सुविधा भी उन्हें दी जा रही है। स्वास्थ्य स्लेट से अभी तक करीब पांच सौ लोगों के स्वास्थ्य की जांच उनके घर पर ही की जा चुकी है।

लोगों के घरों के अलावा अलग से जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी शिविर के दौरान लोगों के टेस्ट करने के साथ–साथ उन्हें मिशन रीव की ओर से दी जा रही सेवाओं की भी जानकारी दी गई। लोगो ने बताया कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है कि घर पर ही टेस्ट हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।

प्रहनुई में खुलेगी क्रिकेट अकादमी

टीम रीव, चंबा

ग्राम पंचायत प्रहनुई खंड व जिला चम्बा में ,पूर्व इंडियन क्रिकेटर व नार्थ जोन बीसीसीआई सिलेक्शन कामेटी के सदस्य विक्रम राठौर ने ग्राम पंचायत में क्रिकेट अकादमी के लिए हाल ही में जमीन का निरीक्षण किया। मिशन रीव के अतिरिक्त खंड समन्यवक नितेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत के युवा काफी समय से इसके लिए मांग कर रहे थे। जब राठौर ने जमीन का मुआयना करने मौके पर पहुंचे तो उनके साथ ग्राम पंचायत प्रहनुई के उप प्रधान संजीव सूरज और स्थानीय व आस पास की पंचायत के युवा उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत प्रहनुई के उप प्रधान संजीव सूरज ने कहा कि पंचायत में क्रिकेट अकादमी खालने के लिए वह लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अकादमी खुलने से खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने का मौका प्रहनुई और आसपास की पंचायतों को मिलेगा।

वहीं पंचायत के युवाओं ने भी पंचायत में अकादमी खुलने पर खुशी जाहिर की है। नितेश का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन सुविधाओं के अभाव में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। अब क्रिकेट अकादमी खुलने से युवाओं को क्रिकेट की बारिकियों को सीखने का मौका मिलेगा और वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे।

पूरे प्रकरण पर क्या कहते है प्रदेश भर मे मिशन रीव से जुड़े युवा

पेज 1 का शेष

"मैं बतौर पीएफ काम कर रहा हूं। आईआईआरडी के साथ काम करने का मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। हमें जो भी कार्य दिया जाता है उसके मुताबिक हमें समय पर मानदेय दिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिशन रीव के तहत गांव तक लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और मिशन में कार्य कर रहे युवाओं को उनके कार्य के मुताबिक समय पर भुगतान भी किया जा रहा है।"

पंकज जिल्टा, मिशन रीव

"मैं पिछले एक साल से मिशन रीव से जुड़ा हूं। कुछ लोग जो काम सही से नहीं कर पाए वह कहते हैं कि उन्हें वेतन नहीं मिला लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें काम के अनुसार पूरा मानदेय आईआईआरडी की ओर से दिया जाता रहा है। अगर कोई समस्या होती है तो उसे तुरंत सुलझा लिया जाता है।"

गोविंद सिंह ठाकुर, एबीसी सलूणी, मिशन रीव

"मिशन रीव के बारे में मुझे इतना कहना है कि इसके माध्यम से मुझे मेरे घर पर ही रोजगार का मौका मिला है। रीव को लेकर कुछ लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि हम भी उन्हीं लोगों के साथ मिशन से जुड़े थे। हमें जो कंपनी ने काम दिए हमनें उसके मुताबिक कार्य किया और हमें समय पर मानदेय भी मिल रहा है।"

विनोद कुमार एबीसी मैहला ब्लॉक, चंबा, मिशन रीव,

"मैं पिछले काफी समय से आईआईआरडी के साथ जुड़ा हूं और मिशन रीव में जुब्बल से बतौर सहायक खंड समन्वयक के तौर पर कार्य कर रहा हूं। मिशन रीव के तहत दी जा रही विभिन्न सेवाओं को हम गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमें उचित मानदेय भी आईआईआरडी की ओर से दिया जा रहा है। इतना ही नहीं मेरे साथ सात पीएफ भी काम कर रहे हैं और उन्हें भी उनके काम के मुताबिक उचित मानदेय दिया जा रहा है।"

गौरव सहायक खंड समन्वयक, मिशन रीव

जिला चंबा के भटियात ब्लाक में जब से मिशन रीव ने नीव रखी है तब से आज तक मिशन रीव धीरे धीरे अपनी ख्याति बड़ा रहा है लोग इसके साथ जुड़ रहे है लोगो को सस्ती दवाई जैनरिक स्टोर के माध्यम से मिल रही है और घर घर लोगो को जरूरतों का सामान पंहुचाया जा रहा है। अभी तक भटियात में किसी का भी मानदेय लंबित नहीं हैं। **कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए मिशन रीव के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं जबकि मिशन रीव से लगातार गांव की तस्वीर बदल रही है।**

अजीत कुमार, मिशन रीव

"मैं बतौर स्वास्थ्य सेवक आईआईआरडी के साथ कार्य कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आईआईआरडी की ओर से मुझे अपने ही गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की का मौका दिया साथ ही रोजगार भी प्रदान किया। हम जो भी काम करते हैं उसके बदले मानदेय समय पर दे दिया जाता है।"

गौरव स्वास्थ्य सेवक, मिशन रीव

क्यों मनाया जाता है छठ पूजा का त्यौहार.... जानते हैं

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दीवाली त्यौहार ख़त्म हो चुका है इसके बाद भाई दूज का त्यौहार और गोबर्धन पूजा भी खत्म हो चुकी है। अब छठ पूजा की शुरुआत है। इस पूजा में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा भारत में भगवान सूर्य की उपासना का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार को षष्ठी तिथि पर मनाया जाता है, जिस कारण इसे सूर्य षष्ठी व्रत या छठ कहा गया है। यह त्यौहार एक साल में दो बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र महीने में और दूसरी बार कार्तिक

महीने में। हिन्दू पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्लपक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ त्यौहार को चौथी छठ कहा जाता है जबकि कार्तिक शुक्लपक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले इस त्यौहार को कार्तिक छठ कहा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यह त्यौहार काफी लोकप्रिय पर्व है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे मुख्य कारण अपने परिवार की खुशी और मनचाहे फल की प्राप्ति है।

दीवाली के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है

आपको बता दें कि दीवाली भारत में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। दीवाली के बाद सबसे बड़ा त्यौहार आता है छठ पूजा । इस पर्व को छठ, छठी, डाला छठ, डाला पूजा, सूर्य षष्ठी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। छठ का भोजपुरी में अर्थ होता है छठा दिन । इस दिन भी हम त्यौहार की तरह सेलेब्रेट करते है।

कार्तिक के महीने में शुरू होता है

आपको बता दें कि छठ पूजा का त्यौहार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है और ये लगातर सप्तमी तक चलता रहता है । मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी के दिन की जाती है। इस दौरान सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उपासना की जाती है । इस दौरान इस तरह से आपको पूजा और आराधना करनी चाहिए।

क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की अराधना की जाती है। सूर्य की भी होती है आराधना हमारे देश में भगवान सूर्य को भी बहुत विशेष दर्जा दिया जाता है। आपको बता दें कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सूर्य की भी पूजा की जाती है। माना जाता है जो व्यक्ति छठ माता की इन दिनों पूजा करता है छठ माता उनकी संतानों की रक्षा करती हैं।

पूरे देश में होती है पूजा

आपको बता दें कि हर तरह के त्यौहारों को मनाने के बाद छठ पूजा का भी अपना एक अलग महत्व होता है। इसको पूरे देश में धूम–धाम से मनाया जाता है । इसके लिए लोग दीवाली से ही तैयारियां शुरु कर देते है ।

छठ पूजा का पावन पर्व, सूर्य अनुकम्पा अपार, रीव का हार्दिक वंधन-मिले सुख-शांति अपार

आओ कानून को जानें

हत्या की कोशिश करने वाले पर लगती है IPC की धारा 307

किसी इंसान की हत्या की कोशिश का मामला अगर सामने आता है, तो ऐसा करने वाले शख्स पर भारतीय कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 लगाए जाने का प्रावधान है। लेकिन इस धारा 307 के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है । आइए आपको जानकारी देते हैं कि क्या है भारतीय दण्ड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड और उसकी धारा 307 ?

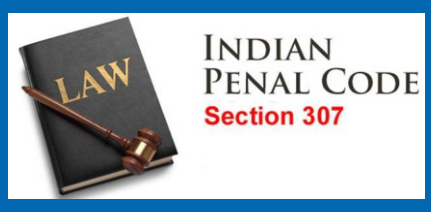

भारतीय दंड सहिंता की धारा 307

जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की हत्या की कोशिश करता है और वह हत्या करने में नाकाम रहता है, तो ऐसा अपराध करने वाले को धारा 307 आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा दिए जाने का प्रावधान है। आसान लफ्जों में कहें तो अगर कोई किसी की हत्या की कोशिश करता है, लेकिन जिस शख्स पर हमला हुआ है, उसकी जान नहीं जाती तो इस तरह के मामले में हमला करने वाले शख्स पर धारा 307 के अधीन मुकदमा चलता है ।

क्या होती सजा

हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को आईपीसी की धारा 307 में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है । आम तौर पर ऐसे मामलों में दोषी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं । जिस आदमी की हत्या की कोशिश की गई है अगर उसे गंभीर चोट लगती है, तो दोषी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है ।

क्या है भारतीय दंड संहिता

भारतीय दण्ड संहिता यानी प्दकपंद च्मदंस ब्वकम, प्च्ब भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा और दण्ड का प्राविधान करती है । लेकिन यह जम्मू एवं कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है । जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता (त्च्ब्) लागू होती है ।

अंग्रेजों की देन है आईपीसी

भारतीय दण्ड संहिता यानी आईपीसी सन् 1862 में ब्रिटिश काल के दौरान लागू हुई थी । इसके बाद समय–समय पर इसमें संशोधन होते रहे । विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया । पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही अपनाया । लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, आदि में भी लागू कर दिया गया था ।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार आईआईआरडी

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है । आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

पीरियड संबंधी समस्याएं

मासिक धर्म, लड़कियों के बड़े होना का एक हिस्सा है । पीरियड आमतौर पर लगभग उसी समय के आसपास शुरू होते हैं, जब शरीर में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन हो रहे होते हैं। मासिक धर्म शुरू करने की औसत आयु 13 साल है, लेकिन 9 साल से 15 साल की उम्र के बीच किसी भी समय शुरू होना सामान्य है । पीरियड्स रजोनिवृत्ति तक चलते हैं, जो आम तौर पर 45 वर्ष की आयु के आसपास होती है । औसत मासिक धर्म चक्र 28 का मानते हैं हांलांकि यह 23 दिनों का होता है ।

मासिक धर्म आपके गर्भाशय के अंतःस्तर का मासिक निस्राव है, जिसके दौरान शरीर से रक्त और ऊतक निकलते हैं। रक्त स्राव पांच दिनों की औसत तक रह सकता है । हालांकि, हर महिला के लिए एक साधारण मासिक चक्र अलग होता है । इसलिए, आपके पीरियड्स में बदलावों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है ।

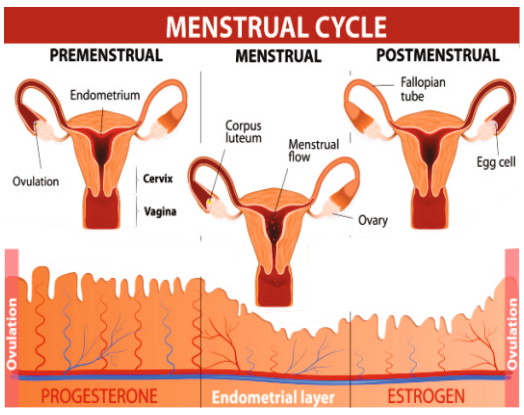

पीरियड संबंधी समस्याएं

विभिन्न प्रकार की मासिक धार्म समस्याएं होती हैं, जिसमें शामिल है:

1. प्री - मेंस्रुअल टेंशन (पी.एम.टी)

यह मासिक धर्म चक्र से जुड़े शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों का एक संग्रह है । लक्षण और उनकी तीव्रता भिन्न हो सकती है। यहाँ तक की, सभी महिलाओं को पी.एम.एस का अनुभव नहीं होता है।

इसके आम लक्षण हैं:

सूजन, चिड़चिड़ापन, पीठदर्द, सिर दर्द, स्तन वेदना,मुँहासे, भोजन की इच्छा, अत्यधिक थकान, अवसाद, चिंता, तनाव की भावनाएं, अनिद्रा, कब्ज, दस्त, पेट में हल्के ऐंठन, पी.एम.एस आपके पीरियड शुरू होने से दो सप्ताह पहले होता है । साथ ही 45 वर्ष की आयु में इस प्रक्रिया के समाप्त होते–होते भी इसी प्रकार की समस्याएं होती है।

2. भारी पीरियड्स:

इसे मेनोरेजिअ या अत्यार्तव भी कहा जाता है । मेनोरेजिअ ज्यादातर हार्मोन के स्तरों में असंतुलन के कारण होता है:

- कुछ दवाओं का उपयोग
- योनि संक्रमण
- गर्भाशय ग्रीवा की सूजन
- अंडरएक्टिव थायरॉयड ग्रंथि (हाइपोथायरायडिज्म)
- गैर कैंसरयुक्त गर्भाशय ट्यूमर (फाइब्रॉएड)
- आहार या व्यायाम में परिवर्तन

3 पीरियड ना आना (रजोरोध) :

यदि एक महिला ने 16 वर्ष की आयु तक भी मासिक धर्म की शुरूआत नहीं की है, तो उसे प्राथमिक रजोरोध है ।

यह पीयूष ग्रंथि की एक समस्या, मादा प्रजनन तंत्र के एक जन्मजात दोष, या यौवन में देरी के कारण हो सकता है । अगर एक महिला छह महीनों या उससे अधिक समय तक पीरियड का अनुभव ना करे, तो इसे माध्यमिक अमानोरिया कहा जाता है। इसके कुछ सामान्य कारण हैं:

- समयपूर्व डिम्बग्रंथि विफलता
- श्रोणि सूजन की बीमारी (एक प्रजनन संक्रमण)
- जन्म नियंत्रण रोकना
- गर्भावस्था
- स्तनपान
- रजोनिवृत्ति
- **4. दर्दनाक पीरियड (कष्टार्तव) :**

पी.एम.एस के दौरान ऐंठन सामान्य है। आम तौर पर असुविधा हल्की होती है और यह एक या दो दिन में कम हो जाती है । लेकिन कुछ महिलाएं इतनी अत्यधिक दर्द महसूस करती हैं कि वे बिस्तर से बाहर तक नहीं निकल पाती । इसके साथ मतली, उल्टी, सिरदर्द या दस्त आदि भी हो सकते है । दर्द फाइब्रॉएड, एंडोमेट्रियोसिस (अन्तर्गर्भाशय – अस्थानता) या पैल्विक सूजन रोग के कारण हो सकता है । व्यायाम दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। डॉक्टर के परामर्श के बिना किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन न करें।

5. बेकायदा पीरियड्स:

एक पीरियड सामान्य रूप से दो से सात दिन तक होता है, औसत पीरियड पांच दिन लंबा होता है। अनियमित पीरियड्स आना युवावस्था के दौरान और रजोनिवृत्ति से ठीक पहले सामान्य हो सकता है। पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (पी.सी.ओ.एस) पीरियड में अनियमितता पैदा कर सकता है। हार्मोनल असंतुलन या गर्भनिरोधक बदलने से भी बेकायदा पीरियड्स हो सकते हैं।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:
therievtime@iirdshimla.org

रीव : रुरलाईजिंग इंडिया-इम्पावरिंग विलेजिज : एक विवेचन

भारतवर्ष अपनी भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताओं के नाते कई प्रकार की संभावनाओं व अवसरों से भरा पड़ा है । यहां तक कि इसकी जनसंख्या भी जहां एक ओर संसाधनों की असमानताओं से जूझती है वहीं एक नया अवसर भी प्रदान करती है । जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याऐं उत्पन्न होती है वे जगजाहिर हैं तथा अब तो राजनैतिक प्राणियों ने भी इस पर बात करनी छोड़ दी, अन्यथा यह राष्ट्रीय मुद्दा अवश्य रहा करता । जब यह वृद्धि इतनी भयावक स्थिति तक पहुंच ही गई है तो इसके होने से जो अवसर पैदा होते हैं उन पर विवेचना की जा सकती है, क्योंकि इसे कम करने के प्रयास तो अब ऊपरवाले के भरोसे हैं ।

अधिक लोगों के होने से सीधा अभिप्राय अधिक उत्पादन का दबाव, अधिक सेवाऐं तथा अधिक व्यवस्थाऐं ! आज के वैज्ञानिक युग में तथा उन्नत होती अर्थव्यवस्था में हमारा जीवन बहुत सारे बाह्य कारकों पर निर्भर हो गया है । जन्म से पहले भावी माता की टीका व पोषण व्यवस्था, जन्म के बाद भी टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, विद्यालय जाने की उम्र में विद्यालय का चयन, पुस्तकें, वर्दी आदि, किशोरावस्था में पढ़ाई पर एकाग्रता तथा मानसिक असंतुलन के ख़तरों से बचाव, यौवन में विवाह व आजीविका संबन्धि विषय, उम्रदराज हो जाने पर परिवार की उचित प्रकार से परवरिश, तदोपरान्त संतान के रोजगार व व्यवसाय तथा गृह निर्माण जैसी प्राथमिकताऐं, बुढ़ापे के उत्तरार्द्ध में स्वास्थ्य, सहयोगी व जीवन त्यागने से जुड़ी चिंताऐं आदि हमारी दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाती हैं। उपरोक्त समस्त कार्यों में यदि दूसरों से वांछित व अनुकूल सहयोग मिलता है तो जीवन सार्थक लगने लगता है अन्यथा व्यक्ति जीवन भर चिंता की अग्नि में जलते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि इन सभी प्रकार की सहयोगात्मक क्रियाओं तथा सेवाओं के लिए कोई व्यवस्था कायम हो जाए तो इससे निःसंकोच जन–साधारण तक को एक सीमित संतुष्टि का एहसास हो सकता है। इसके लिए विशेष सहयोग की आवश्यकता रहती है जो समय पर सबको नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था भी यदि सुनियोजित सेवाओं में हो जाए तो आर्थिक प्रगति बहुत तीव्रता से होने लगे। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं को पाने के कई प्रकार के साधन व संसाधन उपलब्ध होते हैं, गांव वालों के लिए यह कोरी कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं। तेजी से हो रहे शहरीकरण के अनुमान से आज यदि हम मान के चलें कि लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या देश की आज भी गांव में बसती है तो यह आंकड़ा लगभग 85 करोड़ का बैठता है । उपरोक्त आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए यदि अनुमान लगाऐं तो प्रति 500 व्यक्ति एक सेवा आपूर्ति कार्यकर्ता की आवश्यकता रहती है। तदानुसार ग्रामीण भारत को लगभग 17 लाख सेवा आपूर्ति कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जो इस व्यवस्था को प्रदान करने के बाकि लोग प्रबंधकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होंगे, उनकी संख्या भी लगभग 3 लाख के आसपास होगी। इस प्रकार पूरी व्यवस्था में सीधे तौर पर संभवतः 20 लाख लोगों की आवश्यकता रहेगी। यह मात्र सेवा आपूर्ति कार्य व प्रबंधन की बात हुई। इसके अतिरिक्त ऐसे सैंकड़ों व्यवसाय अस्तित्व में आने स्वाभाविक हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की संरचना, गुणवत्ता व रुपरेखा की पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे होंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रामीण बच्चा गणित में कमज़ोर है तो गणित के प्रश्नों को साधारण भाषा में ई–लर्निंग मॉड्यूल में तैयार करने वाले विशेषज्ञ व्यवसायिक निकाय को एक बहुत बड़े शोध एवं विकास दल सहित गांवों में तकनीकी सहयोगकर्ताओं की हज़ारों में आवश्यकता रहेगी। ऐसे ही अन्य अनेक विषयों में भी। एक अंदाजन आकलन से संभव है कि रोजगार का यह आंकड़ा 50 लाख तक जा सकता है । इतनी बड़ी व्यवस्था का तानाबुना इसलिए बनने के आसार हैं क्योंकि पीछे बहुत बड़ी जनसंख्या का एक विशिष्ट सेवा बाजार है ।

इस प्रकार जब लागों के विकासात्मक कार्यों व अन्य सेवाओं में सहयोग समय पर उन्हें मिलना आरंभ होगा तो निश्चित अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्रता मिलेगी। इसी से गांवों का सशक्तिकरण होगा क्योंकि गांवों का सशक्तिकरण मात्र ढांचागत विकास से नहीं होगा अपितु गांवों के लागों की ऊर्जा का विकास की दिशा में जब उपयोग होने लगेगा तथा हर परिवार जब संपन्न बनने के सपने देखने लगेगा – वही गांव के सशक्तिकरण का प्रयाय बनेगा। यही 'इम्पावरिंग विलेजिज' का ध्येय है ।

–2–

अब अगला प्रश्न 'रुरलाईजिंग इंडिया' से जुड़ा है, अर्थात् भारतवर्ष का ग्रामीणिकरण। 'रुरलाईजिंग इंडिया' के बारे में कुछ तथ्य भी इंगित किए जाते रहे हैं कि क्या भारत अधिकतर ग्रामीण स्वतः ही नहीं है, सरकार शहरीकरण की ओर प्रयासरत है तथा कुछ शहरों के विकास से जुड़ीं कुछ केन्द्रिय योजनाओं का भी उल्लेख होता रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद की प्रतिशतता गांवों की अपेक्षा शहर से काफी अधिक है और यह बात सटीक व तर्कसंगत भी है। यहां पर 'रुरलाईजिंग इंडिया' के आशय को मिशन रीव के संदर्भ में जानने की आवश्यकता महसूस होती है।

पहले हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो 'रुरल इंडिया' एक विशेषणयुक्त संज्ञा लगती है। जबकि 'रुरलाईजिंग इंडिया' जब हम कहते हैं तो यहां क्रियात्मक संदर्भ आ जाता है। अर्थात् यहां भारत के ग्रामीणीकरण की बात हो रही है। अब प्रश्न वही कि ग्रामीणीकरण से तात्पर्य क्या ? इससे पहले हम शहरीकरण पर दृष्टि डालते हैं। आज के दौर में गांवों से लोगों का शहरों की ओर तीव्रता से पलायन हो रहा है। शहरों में जैविक दबाव बढ़ता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं, शहर अधिक भीड़–भड़ाके वाले हो गए हैं। गांवों में गुजर–बसर कर रहे तथा समय काटने वाले बुजुर्गों से कोई बात करने वाला भी कहीं उपलब्ध नहीं। जबकि शहरों में भौगोलिक आकार व सुविधाओं की क्षमताओं से अधिक लोगों द्वारा कई प्रकार की आपराधिक वृत्तियों को जन्म दिया जा रहा है। यहां शहरीकरण के दो अलग–अलग कारण हैं। एक तो योजनाबद्ध तरीके से सरकार नए शहरों को बसाना चाहती है या स्थापित शहरों का आकार बढ़ाना चाहती हैं। दूसरा स्थापित शहरों का आयतन अनायास ही स्वतः बढ़ता चला जाता है और नागरिक सुविधाओं के अभाव से कई प्रकार की समस्याऐं पनपनी आरंभ हो जाती है।

सरकारी प्रयासों से शहरों के विकास के लिए जो भी योजनाऐं चलाई गई वे शहरों के सौंदर्यकरण से लेकर उपलब्ध या निकट भविष्य में होने वाली जनसंख्या के लिए आधारभूत सुविधाऐं जुटाने के लिए बनी क्योंकि अधिकांश शहरों की दशा यह हो गई है कि वहां रहना घुटन पैदा करता है। कुछ बड़े व चुनिंदा शहरों को छोड़ आज सामान्य शहरों की परिकल्पना ऐसी बनती है जहां बहुत नज़दीक–2 इमारतें, लोगों की भीड़, सड़कों के आयतन से अधिक गाड़ियों की भरमार, वायु व ध्वनि प्रदूषण की प्रचुरता, अनिश्चितता का परिवेश आदि–आदि।

क्या हम अपनी लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या को ऐसा जीवन जीने के लिए छोड़ सकते हैं , इस पर विचार होना आवश्यक है । दूसरी ओर गांव की वर्तमान परिकल्पना तो बेशक ऐसी हो सकती है कि जहां सड़कें बहुत कम हों, कच्ची व उबड़–खाबड़ हों, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाऐं हो ही न या बहुत सीमित हों, जहां दैनिक जीवनयापन के लिए सुबह से देर रात तक का संघर्ष हो आदि–आदि। लेकिन जब हम रुरलाईज अर्थात् ग्रामीणीकरण की बात करें तो हमें मात्र इतना करना है कि गांवों में सड़कें हो लेकिन हर घर द्वारा तक नहीं अपितु कुछ पैदल भी चलना पड़ें, खेती या खेती जैसा कुछ काम अवश्य हो जहां कुछ शारीरिक श्रम अनिवार्य हो, पेड़–पौधें हो व स्वच्छ वायु हो। घर बहुत समीप न बने हों कि चलने को मार्ग ही कम पड़ जाऐं। जनसंख्या कम हो कि लोगों को मिलने–जुलने व रहने में भी तंगी न हो। ये सब बातें मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ दीर्घायु प्रदान करती हैं ।

अतः आज गांवों को आधारभूत आवश्यकताओं तक ऊपर उठाने की आवश्यकता है लेकिन उनका शहरीकरण न हो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त शहरों में पालायित लोगों को वापस गांवों बुलाने की अनिवार्यता है ही ताकि घुटन के जीवन का त्याज्य कर एक खुले वातावरण में चैन की सांस ले सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आजीविका के साधनों को गांवों में उत्पन्न किया जा सके। जब शहरों से लोग गांवों की ओर विपरीत पलायन करना आरंभ करेंगें, ग्रामीणीकरण का प्रथम अध्याय लिखना आरंभ होगा। दूसरा जो कि काल्पनिक सा लगता है कि क्या शहर भी गांवों की जैसी व्यवस्था में कभी आ पाऐंगें जहां सुविधाऐं तो सभी हों पर ऐसी हो कि लोगों को थोड़ा शारीरिक श्रम भी करना पड़े, जनसंख्या का घनत्व कम हो, सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या कम हो , वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के ख़तरे कम हो, आदि–आदि...। एक बात ये भी समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार नगरीकरण की योजना बनती है, बिल्कुल उसी तर्ज़ पर ग्रामीणीकरण करनी होगी। यानि हम स्मार्ट सिटी की बात तो कर रहे है जबकि हमें स्मार्ट विलेजिज पर भी उसी प्रकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है । जैसे गांव में एक पहाड़ी पर मकान बनाने के लिए लोग निमार्ण कार्य आरंभ करते हैं तो वहां न बिजली होती न सीवरेज की व्यवस्था। यह यदि योजनाबद्ध तरीके से पहले ही हो तो किसी भी कार्य को स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है। यही रुरलाईजिंग का वास्तविक अभिप्राय है ।

यही 'रुरलाईजिंग इंडिया' की विवेचना है जो आगे चलकर 'रुरलाईजिंग इंडिया–इंपावरिंग विलेजिज' की परिकल्पना को मिशन रीव के संदर्भ में पूरी करती है ।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

बलि प्रथा : जीभ के स्वाद में कट रहे हैं बेजुबान

पशुओं को काटते-खाते पशुओं से भी नीच हो गया इंसान

भारतवर्ष की भूमि पवित्रता, चरित्रता, सुसंस्कृति एवं प्रत्येक जीव–जंतु, प्राणियों और कण–कण में ईश्वर को मानने के दर्शन एवं अध्यात्मिक व धार्मिक ढांचे पर आधारित रही है। आस्था कहीं न कहीं हमारे प्रत्येक कियाकलाप का एक प्रमुख अंग है। इस आस्था के कारण ही भारतवर्ष के हर एक मोड़ पर देवी–देवताओं को पत्थरों आदि में स्थापित कर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की जाती है । यह परंपरा अति प्राचीन है। इसे समाज के बुद्धिजीवी अपने–अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। इस परिभाषा में देवी–देवताओं को प्रसन्न करने के अनेक माध्यम भी हमारी इस प्राचीनतम संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। देवताओं की प्रसन्नता को व्यक्ति, परिवार, समाज में खुशहाली लाने और दुःख संकटों से बचने का एक सरल उपाय माना जाता रहा है। अब इसमें देवताओं को पुष्प, अक्षत, दीप आदि तो एक निरंतर और स्थाई प्रकिया का भाग है किंतु देवाताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि (नर अथवा पशु) देना आद्यकालीन समय से ही प्रचलन में देखा जा सकता है। इसे आस्था के साथ इस हद तक जोड़ दिया गया है कि इसे अलग करने मात्र के विचार से अनिष्ट की संभावनाऐं प्रबल हो जाती है। हमारे तथाकथित धर्मानुयायियों और धर्म के ठेकेदारों ने इसे अपने–अपने समय के अनुसार अलग–अलग मोड़ दिए। सारी व्यवस्थाऐं बदलती गई लेकिन निर्जीव हत्या का तांडव आज भी बदस्तूर जारी है। मांस भक्षण एक भिन्न विषय हो सकता है लेकिन उसे देवताओं के नाम पर जीभ के स्वाद से जोड़कर निर्जीव एवं मूक जानवरों की बलि से स्वार्थपूर्ति को जोड़ना, कितनी बुद्धिमता होगी।

देवभूमि हिमाचल और बलि प्रथा

हिमाचल के संदर्भ में यह बात हमें यहां जन्म लेने पर गौरवान्वित करती है कि हम देवभूमि में जन्में और पले–बढ़ें हैं। यहां कण–कण में देवाताओं का वास है। हमारी प्रत्येक गतिविधि, कियाकलाप, रिवाजें, परंपराऐं, अनुष्ठान आदि देवताओं को अर्पित एवं समर्पित होकर ही प्रचलन में आती है। जन्म से लेकर मृत्यु एवं उसके उपरांत भी देवताओं का साथ प्रथम पंक्ति और प्रथम स्थान पर रहता है। ऐसे में प्रदेश की इस दैवीय परंपरा में बलि प्रथा ने अपना स्थान आज भी यथावत बना रखा है। बलि प्रथा के नाम पर हज़ारों पशुओं की बलि धर्म की आड़ में जीभ के स्वाद के लिए दी जा रही है तथा उस पर रोक अथवा विरोध तक नहीं। भेड़–बकरियों को काटने का सिलसिला छोटे–मोटे त्यौहारों से लेकर राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय त्यौहारों तक किया जाता है । इसके लिए बाक़ायदा पैसे इक्टठे कर भेड़–बकरियों को खरीदा भी जाता है तथा उसके बाद शुरु होता है निर्मम जीव संहार.....जो शायद कटने, जलने, भुनने के बाद पेट में अपशिष्ट बनने के बाद भी तृप्ति नहीं दे पाता। यहां यह बात अचंभित करती है कि क्या हमारे संरक्षक, अराध्य और पूजनीय देवगण स्वयं इस बलिप्रथा के संवाहक है ? क्या देवी–देवताओं ने इस बलि प्रथा को मनुष्य से स्वयं को ऊर्जावान बनाने या प्रसन्न करने के लिए मांगा था ? क्या देवी–देवता मांसाहारी होकर जीव हत्या करने के लिए आदेश देते हैं ? ये यक्ष प्रश्न लग रहे होगें लेकिन इसी की

आड़ में कुछ धर्मावलंबी और अंधआस्तिकतावादी अपनी जीभ की लार टपका रहे हैं। क्या यह शास्त्रोक्त है , क्या हमारे धर्मशास्त्र और पुराण इसकी अनुमति देते हैं, इसकी पड़ताल भी आवश्यक है।

क्या कहते है धर्मशास्त्र

हम त्रमुख्यतः पौराणिक एवं प्रमाणिक वेद, उपनिषद एवं श्रीमद्भगवतगीता की बात कर रहे हैं । इन तीनों में ही कहीं भी बलिप्रथा की स्वीकृति नहीं है वरन् इसका विरोध अवश्य ही आता है।

'मा नो गोषु मा नो अश्वेसु रीरिषः।'- ऋग्वेद 1/114/8

अर्थात् : हमारी गायों और घोड़ों को मत मार । ऋग्वेद में यह स्पष्ट कहा गया है कि पशुओं को मारना निषेद और धर्म विरुद्ध है ।

इसी प्रकार यजुर्वेद भी इसका समर्थन नहीं करता :

'इममूर्णायुं वरुणस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जानिन्नमग्ने मा हिंसी परमे व्योम '

अर्थात् : ''ऊन जैसे बालों वाले बकरी, ऊंट आदि चौपायों और पक्षियों आदि दो पगों वालों को मत मार ।'– यजु. 13/50

'न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्यं चरामसि' - सामवेद-2/7

अर्थात् : ''देवों ! हम हिंसा नहीं करते और न ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं, वेद मंत्र के आदेशानुसार आचरण करते हैं' पशुबलि कब से आरंभ हुई इस पर स्पष्ट तो कुछ कहा नहीं जा सकता है । कहा ये भी जाता है कि यज्ञ में आहुति के लिए बलि दी जाती थी । ऐसा कहने वाले धर्मशास्त्रों को ग़लत तरीके से व्याख्यायित करते हैं । वेदों में पांच प्रकार के यज्ञों (ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ) का उल्लेख मिलता है । ऐसा कोई भी विधान नहीं मिलता कि किसी भी इस प्रकार के यज्ञों में बलि मांगी गई हो ।

पशु बलि प्रथा के संबंध में पंडित श्रीराम शर्मा की शोधपरक किताब 'पशुबलि : हिन्दू धर्म और मानव सभ्यता पर एक कलंक' में सभी तथ्यों पर विस्तार से प्रहार किया गया है और एक–एक परत खुलकर सामने रखी गई है । यह अब शाश्वत सत्य है कि और इसे सिद्ध किया भी जा चुका है, किया भी जा रहा है कि कोई भी देवता, ईश्वर का रुप, यज्ञ आदि कभी भी बलि मांगते हैं ।

धर्म की आड़ आख़िर कब तक

देवताओं के कार्यक्रमों में सरेआम पशुबलि देकर हम मानवता का भी अटठाहस करते हैं । हमारे देव हमारे जीवन के ही नहीं समाज के भी संरक्षक और पथ–प्रदर्शक है । हमें जीवन में सही मार्ग पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना करनी हैं और इसके लिए सदाचार, सदभाव, अहिसा, प्रेम से जीवन यापन करना है । इसके लिए देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इस मान्यता पर अधिकतर लोग सहमत होते हैं । तो क्या देवता कभी किसी की हत्या करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं ? यह सचमुच में ही अचंभित करने वाला तथ्य है। मानव आदि काल से ही अपने जीवनयापन के लिए बहुत कुछ करता था यानि उसकी इसे विवशता भी कहा जा सकता था। अपने लिए इसी प्रकार वो जंगली जानवरों को मारता और उसे एक समर्पित भावना से अपनी क्षुद्धाग्नि को शांत करता। धीरे–धीरे यह एक धार्मिक भावनाओं को आत्मसात करते हुए प्रथा बनती गई ।

क्या कहते हैं आचार्य महेश्वर शर्मा :

वेदों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसा विधान कंही भी नहीं है । पशुबलि को न तो कोई शास्त्र स्वीकृति देता है न ही ईश्वर कभी जीव हत्या को प्रमाणित करता है । ये ठीक है कि लोगों ने इसे अपने हिसाब में मंडित किया तथा इसे एक प्रथा के रुप में शुरु कर दिया गया । देवी–देवताओं ने जीव बलि मांगी हो, ऐसा विधान किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता । इसे एक प्रथा के रुप आगे मान्यता देते हुए बढ़ाया गया और यह आज भी प्रचलन में है ।

क्या कहते हैं वेदव्यास आचार्य विनोद शर्मा:

यज्ञ या देवी देवताओं को आधार बनाकर की जाने वाली जीव हत्या एक जघन्य अपराध है। हालांकि वेदों और शास्त्रों में भी इसका खण्डन मिलता है। फिर भी कुछ शास्त्रों में इसका विधान है जहां यज्ञ में पशुबलि दिए जाने का ज़िक्र होता है।

भिन्न मतों के बाद ये समझने की आवश्यकता है कि स्वाद यदि कड़वा होता तो क्या फिर भी मांस भक्षण इसी तरह से बलि की सान पर कटते और मानुष के पेट का भरण करते रहते। एक बड़ा समुदाय आज देव दोष, देवाज्ञा आदि को सामने रख कर निर्मम बेजुबानों की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाते हैं और फिर उसे देवताओं को दिखाकर अथवा तिलक कर अपने पेट की क्षुधा को शांत करते हैं ।

इस विषय पर जब विभिन्न मत रखने वाले लोगों से बात की गई तो गांव में भी इस पशुबलि प्रथा पर अलग–अलग मत सामने आते हैं । ऐसे लोगों की तादात भी बहुत अधिक है जो इस बलि प्रथा का घोर समर्थन करते हैं । उनके अनुसार देवता नाराज़ हो जाते हैं और इसलिए उनको बलि देनी पड़ती है । कुछ इसे सांकेतिक भी मानते है कि बलि तो होनी चाहिए किंतु देवता बलि नहीं खाते । तो प्रश्न यही है कि उसे खाता कौन है ? खा तो मनुष्य रहा है ।

कुल्लु का दशहरा भगवान रघुनाथ जी की पालकी और देवताओं के मिलन के साथ विश्व भर में प्रसिद्ध है । हिमाचल का आकर्षण का केन्द्र भी है । इसमें भी इसी प्रकार बलि दी जाती रही है । कानूनी पेचिदगियों के बाद यथास्थिति के बाद भी वहां की समिति और जनसमुदाय ने पशुबलि न देने का साहसिक एवं प्रशंसनीय निर्णय लिया । इसका स्वागत किया जाना चाहिए ।

ऐसा ही त्यौहार के दौरान शिमला के रामपुर आदि क्षेत्रों में बकरों की बलि दी जाती है जिसकी द रीव टाइम्स को एक शिकायत भी पिछले दिनों फोन पर मिली । वहां के कुछ लोगों ने इस सामुहिक बलि को रोकने के लिए प्रार्थना की । देवताओं के नाम पर आख़िर कब तक हम इन बेजुबानों को स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करेंगे । ये मात्र त्योहारों की बात नहीं है, लोग बच्चा न होने पर देवता की मन्नत बकरे की बलि के साथ रखते हैं । फिर संतान होने पर उस बकरे को सार्वजनिक रुप से काट कर धाम बनाई जाती है और लोगों को खुला निमंत्रण दिया जाता है । इसी प्रकार देवाताओं की जातर में भी सरेआम पशुओं का कत्लेआम किया जाता है ।

हालांकि इसे अधिकारपत्र या आदेशों की कसौटी पर परखने के बजाए अपनी अंतर्रात्मा से पूछा जाना अधिक वाज़िब रहेगा कि क्या खूंटे से बांध कर पशुओं को हमारे ईष्टों और देवताओं के नाम पर काटना–चीरना मनुष्यता के गुणों का परिचायक है ? देवताओं को पुष्प, अक्षत, द्रुवा आदि से प्रसन्न और अधिक ऊर्जावान बनाने की पहल समाजिक ताने–बाने को भी सशक्त बनाता है न कि देवताओं के नाम और उनके माथे पर जीवहत्या को निर्मम रक्त चढ़ाकर स्वयं की क्षुधाग्नि और लालसा को पूरा करने का कुत्सित प्रयास हमें करना चाहिए । ये पशु हमारे समाज और पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण अंग है । इनके जन्म और मृत्यु का भी एक चक्र स्वतः निर्धारित है । मनुष्य को कोई शास्त्र, कोई देवता अथवा ईश्वर रुप जीव हत्या को करने के लिए प्रेरित या स्वीकृति नहीं देता । जिस बकरी, गाय, भैंस का दूध मां के बच्चों की तरह हम पीते हैं, जिस बैल के कांधों पर खेत से सोना निकलता है, जिस भेड़ की ऊन से तन ढककर हम ठंडक दूर करते हैं...ऐसे में इनकी गर्दन पर दराट का प्रहार अपनी जननी के वध से कम नहीं है । आओ ! स्वयं को रोके इस रक्तपात पशुहत्या के जंजाल में लिप्त होने से । एक अहिंसक और सदभाव के समाज का निर्माण हमारे कांधों पर ही है क्योंकि मनुष्य का शरीर कदापि मांसाहार के लिए नहीं बना है । इसलिए पशुबलि का भी कोई औचित्य नहीं है ।

हेम राज चौहान
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com
94184 04334

मनुष्य का शव छूने वाला, घर वापिस आकर नहाता है, फिर कुर्सी पर बैठ कर मरे हुए जानवर का मांस खाता है

बिलासपुर में एम्स के निर्माण के लिए काटे जाएंगे 43 हजार पेड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

एम्स के निर्माण के लिए 1331 बीघा जमीन पर खड़े करीब 43 हजार पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलेगी । बिलासपुर में एम्स के प्रस्तावित होने के साढ़े चार वर्ष बाद वन विभाग ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस केस को तैयार करने के लिए अब जाकर जमीनी औपचारिकताओं को पूरा किया है । वन विभाग बिलासपुर ने पेड़ों की गिनती पूरी कर ली है ।

वन विभाग की जमीन पर लगभग 23 हजार पेड़–पौधे कटेंगे। इसके अलावा अन्य विभागों की जमीन पर करीब 20 हजार पेड़ काटे जाने का अनुमान है। विभाग इन महकमों की भूमि पर भी जल्द पेड़ों की गिनती शुरू करेगा। एम्स के लिए वन विभाग की 538 बीघा जमीन को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस सिलसिले में रेंज ऑफिसर ने डीएफओ बिलासपुर को प्रपोजल भेज दी गई है। इस प्रपोजल में पेड़ों की संख्या और कीमत का संपूर्ण विवरण सौंपा है ।

'जीरो' बजट नहीं अब 'सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि' होगा योजना का नाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

'जीरो' बजट खेती का नाम बदलकर अब 'सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि' रखा जाएगा क्योंकि प्राकृतिक खेती को फिर से परिचित करवाने में पद्म श्री सुभाष पालेकर का अहम योगदान रहा है। कृषि विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी संस्तुति दे चुके हैं। राज्य सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर औपचारिक ऐलान करेगी। दरअसल जिस खेती को जीरो बजट बताया जा रहा है इस पर पशुधन महंगा होने तथा अन्य कृषि इनपुट की कीमत ज्यादा होने से लागत आ रही है। इस लागत को कम करने के लिए सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है।

पशुधन की खरीद को सरकार देगी 53,000 तक का अनुदान

पशुधन की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 53,000 तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को 45,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। चूंकि प्राकृतिक खेती में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके बगैर प्राकृतिक खेती की कल्पना भी नहीं हो सकती इसलिए सरकार गाय की खरीद के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। यह अनुदान देसी नस्ल की रैड सिंधी, थार–पारकर, घीर तथा साहिवाल गाय की खरीद पर ही मिलेगा। देसी नस्ल की गाय का गोबर और गौमूत्र ही प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी बताया जा रहा है ।

योजना से हटा दिया जाएगा जीरो शब्द : मारकंडा

कृषि मंत्री डा. राम लाल मारकंडा ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री से जीरो बजट खेती का नाम बदलने को लेकर चर्चा कर ली है। मुख्यमंत्री भी इस योजना का नाम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती रखने को तैयार हैं। जल्द ही इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। योजना से जीरो शब्द को हटा दिया जाएगा।

देश में पहली बार टनल के भीतर बनेगा रेलवे स्टेशन, हिमाचल में जगह चिन्हित

भारत में पहली बार कोई रेलवे स्टेशन टनल के भीतर स्थापित होगा ।

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मनाली–बिलासपुर–लेह रेल लाइन में जिला लाहौल–स्पीति में इसके लिए जगह चिन्हित की गई है । केलांग स्टेशन के नाम से यह रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध होगा । पहले फेस के लोकेशन सर्वे में केलांग में जगह चिन्हित हुई है। केलांग लाहौल–स्पीति जिला का मुख्यालय है। लेह तक रेल पहुंचाने का मकसद चीन की सीमा तक पहुंचना भी है । चीन ने दूसरी तरफ से भारत की सीमा तक सड़कें बनाने के साथ–साथ रेल लाइन भी बिछाई हुई है । भारत भी इस दिशा में आगे बढ़कर सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हुए कई और अहम पग आगे बढ़ाएगा ।

20 घंटे में होगा दिल्ली से लेह तक का सफर

दिल्ली से लेह तक का सफर आम तौर पर करीब 40 घंटों में तय होता है । रेल लाइन बिछने के बाद यह सफर 20 घंटों में तय किया जा सकेगा। इंडो–तिब्बतियन बॉर्डर से केलांग की दूरी 120 किलोमीटर है । इस बिलासपुर–लेह रेल लाइन से सुंदरनगर, मंडी, मनाली, केलांग, कोकसर, दारचा, उपसी व कारो सहित हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के कई स्थान जुड़ेंगे । चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न रेलवे डी.आर. गुप्ता के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 54 टनलें, 124 मेजर ब्रिजिज व 396 माइनर ब्रिजिज बनेंगे । पहले फेस के सर्वे के मुताबिक टनलों और पुलों की यह संख्या तय हुई है

30 माह में पूरा होगा फाइनल लोकेशन सर्वे

नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर विश्वेष चौबे के मुताबिक फाइनल लोकेशन सर्वे को पूरा करने की अवधि 30 माह रहेगी और उसके साथ ही इसकी डी.पी.आर. तैयार हो पाएगी । दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में कई रेलवे स्टेशन हैं। टनल के भीतर ही तैयार होने वाला केलांग का यह रेलवे स्टेशन देश में अपनी तरह का पहला स्टेशन होगा । समुद्र तल से इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक होगी ।

लेह और लाहौल-स्पीति में बढ़ेगा पर्यटन कारोबार

इस रेल लाइन के तैयार होने से लेह और लाहौल–स्पीति की ओर पर्यटन कारोबार बढ़ेगा । सेना की कॉनवाई भी इसी रेल लाइन से आगे बढ़ सकेगी । मौजूदा दौर में सैन्य वाहन रोहतांग दर्रे से गुजर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में रोहतांग टनल को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा । उसके साथ ही रेल लाइन बिछने के बाद सुविधाओं में और इजाफा होगा ।

राजधानी में चिट्टे और चरस के साथ छात्र समेत 7 गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पुलिस ने चिट्टे और चरस के दो मामलों में सात युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक कॉलेज छात्र भी शामिल हैं । पुलिस ने ढली के पास चार युवकों से 3.27 ग्राम चिट्टा और दूसरे मामले में पंथाघाटी के पास तीन युवकों से 44 ग्राम चरस पकड़ी।

पुलिस ने मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है । करीब साढ़े छह बजे पुलिस की टीम ढली बाईपास सड़क पर गश्त पर थी । इसी दौरान लंबीधार के पास एक गाड़ी पहाड़ी की ओर खड़ी थी और कुछ युवक इसमें नशे के पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे थे ।

पुलिस ने जब इन युवकों से पूछा तो वह घबरा गए । इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो प्रदीप (26), विकास कंवर (25) दिनेश (26) और नविंद्र कंवर (27) से 3.27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ । पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया । इसमें तीन युवक ठियोग के रहने वाले हैं जबकि एक युवक भट्टाकुफर का निवासी है।

आईआईआरडी ने पहले ही पूरे प्रदेश छेड़ रखा है नशामुक्त अभियान

आईआईआरडी ने पूरे प्रदेश में पहले ही नशे के खिलाफ एक प्रदेश्व्यापी अभियान छेड़ रखा है जिसका प्रथम चरण सफलता के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में संपन्न किया था । संस्था अब प्रदेश में दूसरे चरण में युवाओं को परामर्श एवं अन्य माध्यमों से नशे की लत से छुड़ाने के लिए अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है ।

हिमाचल समेत चार राज्यों के आलू बीज पर प्रतिबंध, ये है वजह

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल समेत उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में पैदा होने वाले आलू बीज पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है । केंद्रीय एजेंसी के सर्वे में इन राज्यों के आलू बीज में सूत्र कृमि (निमेटोड) पाया गया । इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इससे लाखों किसानों को झटका लगा है। देश के प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों में शुमार हिमाचल के लाहौल–स्पीति, बरोट और कुफरी में सबसे ज्यादा आलू बीज तैयार किया जाता है। हालांकि, केंद्र ने इतनी छूट दी है कि ये राज्य आलू को खाने के लिए बेच सकते हैं, वहीं खाने वाले आलू का भी उत्पादन कर सकते हैं और बाहरी राज्यों में बेच सकते हैं । आलू में सूत्र कृमि होने से मानव जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है।

सूत्र क्रीमी से आलू बीज की पैदावार करीब दस फीसदी तक कम रहती है और इसे बीजने से जमीन भी खराब होती है। हिमाचल में किसान प्रमुख रूप से हिमालनी, गिरिधारी, ज्योति, चंद्रमुखी आदि आलू की प्रमुख किस्में तैयार करते हैं।

लाहौल घाटी में ही करीब डेढ़ हजार हेक्टेयर भूमि पर आलू बीज का उत्पादन होता है। इस बार लाहौली आलू बीज की करीब 2 लाख बोरियां देश की मंडियों में पहुंच चुकी हैं।

बेहतर गुणवत्ता के कारण लाहौल के आलू बीज की पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत पंजाब, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों से मांग रहती है।

हिमाचल को डीजीपी हटाने का अधिकार

देश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, पुलिस एक्ट-2007 का दिया हवाला

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर राज्य के डीजीपी को हटाने का प्रावधान है । इसके लिए पांच सदस्यीय सिविल सर्विस बोर्ड पुलिस एक्ट के तहत निर्णय लेने के लिए अधिकृत है । जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा था कि डीजीपी को नहीं हटाया जा सकता है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा और नियुक्ति यूपीएससी की सिफारिशों पर निर्भर करेगी । कोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पुलिस एक्ट–2007 के तहत हिमाचल में डीजीपी को किसी भी समय हटाया जा सकता है । इसके अलावा डीजीपी के दो साल के कार्यकाल की भी बंदिश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार ने कहा है कि वर्ष, 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को पुलिस एक्ट बनाने के आदेश पारित किए थे । इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 2007 में पुलिस एक्ट को मंजूरी प्रदान कर इसे लागू कर दिया है । पुलिस एक्ट का हवाला देते हुए हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष मजबूती से रखा है । इसमें कहा गया है कि पुलिस एक्ट के अनुसार सिविल सर्विसज बोर्ड डीजीपी की नियुक्ति के लिए पात्र तीन–चार अधिकारियों का पैनल तैयार करेगा । इस आधार पर बोर्ड डीजीपी की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को करेगा । पुलिस एक्ट के अनुसार डीजीपी के कार्यकाल की कोई शर्त नहीं है । इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर डीजीपी को किसी भी समय हटाया जा सकता है । अब सुप्रीम कोर्ट को हिमाचल सरकार के इस पक्ष पर अपना अंतिम फैसला सुनाना है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी को दो साल से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। मसलन किसी राज्य में यदि डीजीपी की नियुक्ति 59 साल की आयु में होती है तो उसका कार्यकाल 61 वर्ष की आयु तक रहेगा । इस आधार पर राज्य सरकार डीजीपी के लिए उन्हीं अधिकारियों का पैनल भेजे, जिनका सेवाकाल दो वर्ष शेष रहता हो । यह पैनल यूपीएससी को भेजा जाएगा । इस प्रक्रिया के तहत यूपीएससी की सिफारिश पर राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति होगी ।

आवेदन के रूप में देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के जवाब पर इसे आवेदन के रूप में लाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसके लिए आवेदन करें कि पुलिस एक्ट के तहत डीजीपी को हटाने और नियुक्ति का अधिकार है।

सामान्य ज्ञान : हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहां पर है?
(च). कल्पा (ठ). केलांग (ब). सोलन
(क). नाहन
उत्तर (ठ). केलांग

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है?
(च). मंडी (ठ). सोलन (ब). सिरमौर
(क). ऊना
उत्तर (क). ऊना

हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है?
(च). कांगड़ा (ठ). बिलासपुर (ब). चंबा
(क). हमीरपुर
उत्तर (च). कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
(च). सोलन (ठ). शिमला (ब). लाहौल स्पीति
(क). कांगड़ा
उत्तर (ब). लाहौल स्पीति

प्रदेश में किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है?
(च). उन्ना (ठ). कांगड़ा (ब). मंडी
(क). कुल्लू.
उत्तर (ठ). कांगड़ा

प्रदेश में सबसे अधिक पंचायत वाला जिला कौन सा है?
(च). बिलासपुर (ठ). कांगड़ा (ब). उना
(क). चंबा.
उत्तर (ठ). कांगड़ा

प्रदेश में सेब उत्पादन में प्रथम जिला कौन है?
(च). बिलासपुर (ठ). शिमला (ब). ऊना
(क). चंबा
उत्तर (ठ). शिमला

हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे?
(च). कर्नल एन सी मेहता
(ठ). जनरल वीके शर्मा
(ब). मेजर सोमनाथ शर्मा
(क). ले जन आर सी मेहता
उत्तर (ब). मेजर सोमनाथ शर्मा

हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है?
(च). चंबा न्यूज (ठ). हिम रक्षक
(ब). हिम संवाहक (क). गिरिराज.
उत्तर (क). गिरिराज

हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था?
(च). शिमला (ठ). सोलन (ब). बिलासपुर
(क). ऊना
उत्तर (च). शिमला

हिमाचल देश का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र कौन से जिले में स्थित है?
(च). चंबा (ठ). ऊना (ब). शिमला
(क). बिलासपुर
उत्तर (क). बिलासपुर

दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति के साथ है ?
(च). श्याम क्रांति (ठ). हरित क्रांति
(ब). श्वेत क्रांति (क). भूरी क्रांति
उत्तर (ब). श्वेत क्रांति

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस चीज से है?
(च). साक्षरता (ठ). खाद (ब). मत्स्य (क). दुग्ध
उत्तर (च). साक्षरता

हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है?
(च). लामा झील (ठ). सूरज ताल
(ब). चंद्रताल (क). रेणुका
उत्तर (क). रेणुका

हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थित हैं?
(च). मंडी (ठ). शिमला (ब). कुल्लू
(क). सोलन
उत्तर (क). सोलन

नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है?
(च). शिमला (ठ). पालमपुर (ब). नाहन
(क). सोलन.
उत्तर (ठ). पालमपुर.

विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने दिया इस्तीफा

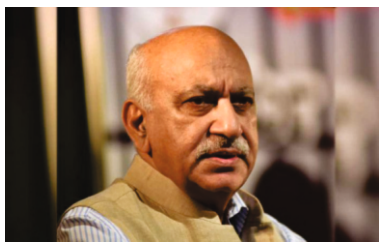

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मी टू आरोपों से घिरे विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को इस्तीफा दे दिया. उनके ऊपर अब तक 20 महिला पत्रकारों ने मी टू अभियान के तहत आरोप लगाए हैं। इससे पहले एमजे अकबर ने 14 अक्टूबर 2018 को अपने आधिकारिक विदेश दौरे से देश वापसी पर बयान जारी कर आरोपों पर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

अकबर पर पहला आरोप वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने लगाया था, जिसमें उन्होंने एक होटल के कमरे में इंटरव्यू के दौरान की अपनी कहानी बयां की थी। भाजपा सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में पहली बार किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है। अकबर अंग्रेजी अखबार 'एशियन एज' के पूर्व संपादक भी रहे हैं। सबसे पहले प्रिया रमानी ने उनके खिलाफ आरोप लगाया था और बाद में धीरे–धीरे और 19 महिला पत्रकार भी अपनी शिकायतों के साथ खुलकर सामने आ गई थीं।

अकबर दैनिक अखबार 'द टेलीग्राफ' और पत्रिका 'संडे' के संस्थापक संपादक रहे अकबर वर्ष 1989 में राजनीति में आने से पहले मीडिया में एक बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते थे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य अकबर जुलाई 2016 से विदेश राज्य मंत्री थे।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अकबर का इस्तीफा स्वीकार किया

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर 17 अक्टूबर 2018 को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से एमजे अकबर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में बताया गया की राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध (2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर केन्द्रीय मंत्री परिषद से एमजे अकबर का इस्तीफा स्वीकार लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अकबर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप उसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया।

मी टू मूवमेंट:

अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ मी टू हैशटैग दो महीने से भी कम समय में टाइम (अंग्रेज़ी पत्रिका) के लिए पर्सन ऑफ द ईयर बन गया। एलिसा मिलानो नामक अभिनेत्री ने हॉलीवुड के फिल्म निर्माता हार्वी वाइंस्टाइन के खिलाफ सबसे पहले अपनी बात कही थी।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद का चुनाव जीता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का चुनाव जीत लिया है। एशिया–प्रशांत श्रेणी में भारत को 188 देशों का समर्थन मिला। इस जीत के साथ भारत को 12 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार परिषद का तीन साल के लिए सदस्य चुन लिया गया है. भारत का कार्यकाल 01 जनवरी 2019 से शुरू होगा।

भारत को सबसे ज्यादा वोट:

भारत एशिया–प्रशांत क्षेत्र श्रेणी में था। 18 नए सदस्यों में भारत को सबसे ज्यादा 188 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा में मानवाधिकार परिषद के नए सदस्यों को चुना गया। 18 नए सदस्यों को गुप्त मतदान द्वारा पूर्ण बहुमत के आधार पर चुना गया। परिषद में चुने जाने के लिए किसी भी देश को कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है।

कुल पांच सीटें

एशिया–प्रशांत क्षेत्र से मानवाधिकार परिषद में कुल पांच सीटें हैं जिनके लिए भारत के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, फिजी और फिलीपीन ने अपना नामांकन भरा था।

भारत पहले भी 2011–2014 और 2014 से 2017 दो बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है। भारत का अंतिम कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुआ था। यूएन के नियमानुसार, लगातार दो कार्यकाल के तुरंत बाद कोई देश तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता।

यूएनएचआरसी में कुल सदस्य देश:

यूएनएचआरसी में कुल 47 निर्वाचित सदस्य देश हैं। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सदस्यों को पांच क्षेत्रीय समूहों में बांटा गया है। अफ्रीकन स्टेट्स में 13 सदस्य, एशिया–पेसिफिक में 13 सदस्य, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में 6 सदस्य, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स में 8–8 सदस्य, जबकि वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य स्टेट्स के लिए 7 सीटें निर्धारित हैं.

ये देश नए सदस्य बने:

चुनाव के बाद अफ्रीका क्षेत्र के नए सदस्य बुर्किना फासो, कैमरून, इरिट्रिया, सोमालिया और टोगो बने हैं। ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप में बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक ने जीत दर्ज की। लैटिन अमेरिका और कैरेबिया क्षेत्र में अर्जेंटीना, बहामास और उरुग्वे शामिल हैं। वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य राज्यों की कैटेगिरी में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली नए सदस्य बने हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946–47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य–प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च 2006 को एक नई मानवाधिकार परिषद् के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद् ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है।

पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया 'हरित दिवाली-स्वस्थ दिवाली'

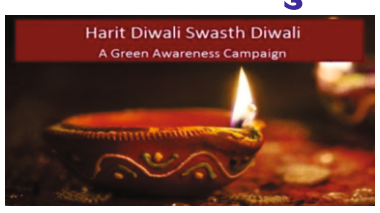

वायु प्रदूषण सर्दियों के दौरान देश में, विशेषकर उत्तरी हिस्सों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप धारण कर लेता है जिसके चलते पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली–स्वस्थ दिवाली' अभियान का शुभारंभ किया है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखे भी वायु प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। दीपावली के दौरान चलाए जाने वाले पटाखों में कई ज्वलनशील रसायन होते हैं जिनमें पोटेशियम क्लोरेट पाउडर वाला अल्युमीनियम, मैग्नीशियम, बेरियम, तांबा, सोडियम, लिथियम, स्ट्रोंटियम इत्यादि शामिल होते हैं। इन प्रतिकूल प्रभावों के साथ–साथ दीपों के त्योहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 'हरित–दिवाली' अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के तहत बच्चों को अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को मिठाइयों सहित पौधे उपहार स्वरूप देने और अपने घरों एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की सलाह दी जाती है। 'हरित दिवाली–स्वस्थ दिवाली' अभियान का विलय 'ग्रीन गुड डीड' अभियान में कर दिया गया है जिसका शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक एकजुटता के रूप में किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ वर्ष 2017–18 में हुआ था।

भारत के प्रधानमंत्रियों पर दिल्ली में संग्रहालय

भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक संग्रहालय के निर्माण के लिए दिल्ली में आधारशिला रखी गई। भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक संग्रहालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में तीन मूर्ति एस्टेट पर प्रस्तावित संग्रहालय की आधारशिला रखी।

तीन मूर्ति एस्टेट के 23 एकड़ क्षेत्र में "भारत के प्रधानमंत्रियों पर एक संग्रहालय" स्थापित करने का फैसला किया गया है जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। संग्रहालय इमारत परिसर का निर्मित क्षेत्र 10975.36 वर्ग मीटर होगा जिसमें 271 करोड़ रुपये की लागत से सभी स्तरों पर गैलरियों के साथ बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल होगा। ऊर्जा मंत्री ने 'सौभाग्य' के अंतर्गत पुरस्कार योजना लांच की।

विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने बिजली वितरण कम्पनियों/राज्यों के विद्युत विभाग तथा उनके कर्मचारियों को संचालन क्षेत्र में 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद देने के लिए 15 अक्टूबर 2018 नई दिल्ली में सौभाग्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार योजना की घोषणा की। यह पुरस्कार बिजली वितरण कम्पनियों डिस्कॉम/राज्यों के विद्युत विभागों के स्तर पर 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिए जाएंगे। सौभाग्य लांच होने के पहले 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और तमिलनाडु) ने 99 प्रतिशत से अधिक घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और यह राज्य पुरस्कार योजना में शामिल होने योग्य बन गए हैं।

सौभाग्य योजना:

केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) लांच किया था. इसका उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना था. इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है।

केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण बॉन्ड योजना जारी की गई

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि तय कार्यक्रम के तहत सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक हर महीने जारी की जाएगी। गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मनोनीत डाकघरों एवं मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई लिमिटेड के जरिए की जाएगी। योजना का पहला चरण निवेश के लिए 15 अक्टूबर को खुला और 19 अक्टूबर को बंद हो गया। तो वहीं बॉन्ड 23 अक्टूबर को जारी किया गया।

स्वर्ण बॉन्ड योजना

इस योजना के तहत कम से कम एक ग्राम सोना और अधिक से अधिक पाँच सौ ग्राम सोने के वज़न के मूल्य के बराबर बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।

इस योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी. इसका उद्देश्य भौतिक रुप से सोने की मांग में कमी लाना एवं सोने की खरीद में उपयोग होने घरेलू बचत का इस्तेमाल वित्तीय बचत में करना है। घर में सोना खरीद कर रखने की बजाय अगर आप सॉवरेन गोल्डल बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं।

पूरे भारत में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से पूरे भारत में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में भारत के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अलग–अलग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक भारतीयों के पास एक से ज्यादा लाइसेंस हैं। इसीलिए अब सभी का लाइसेंस एक जैसा होगा। जुलाई 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा में होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह होंगे।

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने बजरंग पूनिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने 22 अक्टूबर 2018 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। जापान के ताकुटो ओटुगुरो ने उन्हें पुरुषों के 65 किलोग्राम वेट कटिगरी के फाइनल में 16–9 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

पूनिया इस हार के बावजूद रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। वह इस टूर्नामेंट में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बजरंग पूनिया ने इसी वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वे एशियन गेम्स में कुश्ती में यह मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे।

नोवाक जोकोविच ने चौथी बार जीता शंघाई मास्टर्स ओपन ख़िताब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक को 6–3, 6–4 से हराकर 14 अक्टूबर 2018 को चौथी बार शंघाई मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया। दूसरी सीड जोकोविच ने पुरुष एकल के फाइनल में 13वीं सीड कोरिक को एक घंटे 37 मिनट में पराजित किया। इससे पहले जोकोविच ने वर्ष 2012, वर्ष 2013 और वर्ष 2015 में जीत हासिल किया था।

इस खिताबी जीत के बाद जोकोविच विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज राफेल नडाल के रैंकिंग अंक के करीब पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में चल रहे 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच का यह लगातार 18वीं जीत है।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी का निधन

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का 18 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। एनडी तिवारी का निधन उनके जन्मदिन के दिन हुआ। वे 93 वर्ष के थे।

नारायण दत्त तिवारी देश के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें दो–दो राज्य का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे नेहरू–गांधी के दौर के उन चंद दुर्लभ नेताओं में थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान दिया। वे उत्तर प्रदेश के तीन बार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। एनडी तिवारी का पूरा नाम नारायण दत्त हैं। एनडी तिवारी का पूरा नाम नारायण दत्त तिवारी था। एनडी तिवारी देश के वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और विदेशमंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वे वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे।

डब्ल्यूईएफ इंडेक्स में भारत 58वें नंबर पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने 16 अक्टूबर 2018 को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं वाली 2018 की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूचि में भारत 58वें नंबर पर है। सूची में अमेरिका इस साल शीर्ष पर रहा। वर्ष 2008 के बाद अमेरिका पहली बार नंबर–1 पर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि वर्ष 2017 के मुकाबले भारत के स्थान या रैंकिंग में पांच अंकों का सुधार हुआ है. इस रिपोर्ट में भारत 62 अंकों के साथ 58वें स्थान पर है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में 140 देश शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी 140 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में अमेरिका के बाद सिंगापुर दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है. वहीं, सूची में पड़ोसी देश चीन को 28वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी क्षेत्रों में आगे है। इन क्षेत्रों में श्रीलंका भारत के मुकाबले आगे है। द्वीपीय देश में सेहतमंद जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष है और वहां के कामगारों में शिक्षा भी बेहतर है। विश्व आर्थिक मंच की इस सूची में शीर्ष–10 देशों में अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, हांगकांग, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)

विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर–लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी–सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तर पर होती है और ये स्तर उनकी संस्था के कार्य कलापों में सहभागिता पर निर्भर करती है। सदस्यता के लिए वह कंपनी चुने जाते हैं जो विश्व भर में अपने उद्योग में अग्रणी होते हैं अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे होते हैं।

ब्रह्मोस के मुकाबले चीन ने सुपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एक तरफ भारत में परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम राफेल विमान पर विवाद जारी है, वहीं पड़ोसी देश चीन की एक खनन कंपनी ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है । बताया जाता है कि भारत–रूस के संयुक्त उपक्रम से बनी ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले में इसे तैयार किया गया है । चीनी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान अब यही एचडी–1 सुपरसोनिक मिसाइल चीन से खरीदने जा रहा है ।

चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार विगत सोमवार को उत्तरी चीन के एक गुप्त स्थान पर इस मिसाइल का शक्ति परीक्षण किया गया । दक्षिण चीन स्थित ग्वांगदोंग होंडा ब्लास्टिंग कंपनी के जारी बयान के अनुसार परीक्षण के दौरान सभी पैमानों पर एचडी–1 सुपरसोनिक मिसाइल खरी उतरी है।

बीजिंग के सैन्य विशेषज्ञ वी डोंजू ने बताया कि खनन कंपनी ने स्वतंत्र रूप से एचडी–1 मिसाइल में निवेश कर उसे विकसित किया है । इस मिसाइल को युद्धक विमानों और युद्धपोतों में तैनात किया जा सकता है । इस मिसाइल में चीनी कंपनी ने 18.8 करोड़ डॉलर का निवेश किया है ।

ब्लड टेस्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत, कुत्ता सूंघकर ही बता देगा आपको मलेरिया है या नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

कुत्ते की नाक मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है । अमेरिकन सोसायटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बिना लक्षण के कुत्ते मोजे को सूंघकर बता सकते हैं कि व्यक्ति को मलेरिया है । कुत्तों में सूंघने की क्षमता मनुष्य के मुकाबले एक हजार गुना अधिक होती है । इसके नतीजतन वह मलेरिया संक्रमित व्यक्ति की सांसों और उसकी त्वचा से पैदा होने वाली गंध से पहचान कर सकता है । यह तरीका भविष्य में काफी किफायती साबित होगा ।

इनमें भी महारत हासिल

न केवल मलेरिया कुत्ते प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर और मधुमेह जैसी जानलेवा बीमारियों का भी सूंघकर सटीकता से पता लगा सकते हैं ।

मलेरिया मुक्त देश

श्रीलंका, पेराग्वे, क्यूबा, मालदीव, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और मोरक्को ।

इकोनॉमिक कॉरिडोर से बस सेवा शुरू कर सकते हैं चीन-पाक, भारत ने जताई आपत्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

पाकिस्तान और चीन बस सेवा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। यह बस चीन–पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) से गुजरेगी। सीपीईसी, पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरेगा। इसलिए भारत ने चीन–पाक के बीच प्रस्तावित इस बस सेवा पर आपत्ति जताई है । सीपीईसी के पीओके से गुजरने के चलते भारत पहले से इसका विरोध जताता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि चीन और पाक के बीच शुरू होने वाली बस सेवा भारत की संप्रभुता (सॉवेरीनटी) और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के लाहौर से चीन के काशगर तक 13 नवंबर से बस सेवा शुरू होगी।

55 साल पहले चीन-पाक के बीच हुआ समझौता अवैध

रवीश कुमार के मुताबिक, '1963 का तथाकथित चीन–पाकिस्तान सीमा समझौता अवैध और अमान्य है और भारत सरकार द्वारा इसे कभी मान्यता नहीं मिली । अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर से कोई बस सेवा शुरू होगी तो यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन होगा'

दुनिया के सबसे लंबे सी-ब्रिज पर लगे हैं एक्स-रे कैमरे ड्राइवर ने जम्हाई भी ली तो करेगा अलर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- पुल को बनाने में करीब 60 आइफिल टॉवर के बराबर स्टील इस्तेमाल किया गया
- तूफान और भूकंप में भी खड़ा रह सकने के लिहाज से डिजाइन हुआ

द रीव टाइम्स ब्यूरो : चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को झुहाई से दुनिया के सबसे बड़े सी–ब्रिज का उद्घाटन किया । 55 किमी लंबा यह पुल चीन के झुहाई को हॉन्गकॉन्ग और मकाऊ को जोड़ता है । चीनी अधिकारियों ने इसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल बताया है । हॉन्गकॉन्ग के मीडिया का दावा है कि पुल में मॉनिटरिंग इतनी तेज है कि अगर ड्राइवर 20 सेकंड के अंतराल में तीन बार भी जम्हाई लेता है तो कंट्रोल रूम उसे तुरंत अलर्ट कर देता है ।

45 मिनट में पूरा होगा 4 घंटे का सफर, कूटनीतिक तौर पर भी अहम है पुल

हॉन्गकॉन्ग और ताइवान के बीच तनाव रहा है । दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर के इलाकों पर अपना अधिकार बताता है । पुल को क्षेत्रीय स्तर पर चीन की लीडरशिप की बढ़ती दखलअंदाजी के तौर पर भी देखा जा रहा है ।

दक्षिण चीन, हॉन्गकॉन्ग और ताइवान का इलाका आर्थिक रूप से काफी मजबूत है । यह चीन की कुल भूमि के मुकाबले महज 1प्रतिशत है, लेकिन इस क्षेत्र की चीन के कुल घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है । लिहाजा चीन यहां ज्यादा विकास करने के बारे में सोच रहा है।

अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करने के लिए इस एजेंसी को चाहिए वॉलनटिअर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

स्पेस यानी अंतरिक्ष में बच्चे की डिलिवरी का आइडिया किसी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर का प्लॉट लग सकता है । हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 6 सालों में ऐसा मुमकिन हो सकता है । स्पेसलाइफ ऑरिजिन ने घोषणा की है कि वह 2024 तक स्पेस में पहले बच्चे की डिलिवरी की तैयारी में है । एजेंसी को इसके लिए वॉलनटिअर्स की तलाश है ।

सलाइफ ऑरिजिन्स के फाउंडर और सीईओ कीज मल्डर ने कहा कि अगर मानवता मल्टिप्लेनेटरी (बहुग्रहीय) प्रजाति बनना चाहती है तो हमें स्पेस में प्रजनन के तरीके सीखने की भी आवश्यकता है । फर्म का दावा है कि वह एक अंतरिक्ष. भ्रूण–इनक्यूबेटर बना रही है जिसे 2021 में अंडे और स्पर्स के साथ स्पेस में भेजा जाएगा ।

एजेंसी के मुताबिक अंडे और स्पर्म के मेल से स्पेस में भ्रूण विकसित होना शुरू हो जाएगा । हालांकि उन्होंने इसकी प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया । 4 दिनों बाद इन्क्यूबेटर धरती पर लौट आएगा और यहां पर असल गर्भावस्था और प्रसव यहीं संपन्न होगा । फर्म ने बताया है कि 2024 में उसने स्पेस में पहले प्रसव की योजना बनाई है।

फर्म के प्रवक्ता ने बताया कि 24–36 घंटे के एक मिशन में धरती से 250 मील ऊपर एक महिला बच्चे को जन्म देगी । उस दौरान महिला के साथ ट्रेंड और वर्ल्ड क्लास मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि सावधानी से तैयार किया गया और देखरेख में पूरी की गई इस प्रक्रिया में सभी संभावित खतरों से निपटने का उपाय होगा ।

जब शहर में मिला दूसरे वर्ल्ड वार का विशाल जिंदा बम, लोगों में मच गया हड़कंप

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रेलवे स्टेशन के पास वर्ल्ड वॉर 2 के समय का बम मिला है । शहर में निर्माण कार्य के लिए खुदाई के दौरान यह बिना फटा हुआ जिंदा बम पाया गया । 1100 पाउंड का विशाल बम मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के 800 मीटर के इलाके को खाली करा लिया। जर्मनी में एक रेलवे स्टेशन के पास वर्ल्ड वॉर 2 के समय का बम मिला है । बीते शुक्रवार को बर्लिन शहर में निर्माण कार्य के लिए खुदाई के दौरान यह बम मिला ।

बर्लिन शहर का बम निरोधक दस्ता तुरंत इस बात की सूचना पाकर मौके पर बम को नाकाम करने के लिए पहुंचा । यह 1100 पाउंड का विशाल बम था । बिना फटा हुआ जिंदा बम मिलने के बाद शहर की पुलिस ने बम मिलने वाली जगह के 800 मीटर आसपास के इलाके को खाली कराया ।

बम निरोधी दस्ते ने बम की जांच की और इलाके को खतरे से पूरी तरह महफूज किया। इसके बाद दस्ते के लोगों ने बम के साथ यह तस्वीर भी क्लिक करवाई ।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

द रीव टाइम्स
संस्थापकः डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स
पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक
श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस
सायबू निवास समीप सेक्टर -2 ,
बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9,
हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादकः डा. एल.सी. शर्मा,
प्रबन्ध सम्पादकः आनन्द नायर
फोन न. 0177 2640761,
मेलः editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

करेंट अफेयर्स क्विजः

1. वर्ष 2008 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के वैज्ञानिक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया?
a- जेकॉब मुरिमिच b- रेकॉब हसानोई
c- ओकूमा शिन्गोबू d- ओसामू शिमोमुरा

2. निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2018 का खिताब जीता?
a- पीवी सिंधू b- ताई जू यिंग
c- साइना नेहवाल d- एंजलिना कर्बर

3. हाल ही में किस देश की एक कंपनी ने हफ्ते में कम–से–कम 5 दिन 6–6 घंटे की नींद रात के वक्त लेने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया है?
a- स्वीडन b- स्विट्जरलैंड
c- चीन d- जापान

4. निम्नलिखित में से किस राज्य में 46 संगठनों ने केंद्र सरकार के नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के खिलाफ राज्यव्यापी बंद बुलाया है?
a- पश्चिम बंगाल b- असम
c- सिक्किम d- केरल

5. विश्व कुश्ती चौंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है?
a- सौरभ चौधरी b- योगेश्वर दत्त
c- बजरंग पूनिया d- आशीष वत्सल

6. दीपावली के अवसर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिये पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की?
a- सुरक्षित दिवाली अभियान
b- हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली अभियान
c- बिना पटाखे दिवाली, हर ओर उजियारा अभियान
d- पर्यावरण हितैषी दिवाली अभियान

7. किस राज्य सरकार ने सर्वानंद प्रेमी द्वारा लिखित 'श्रीमद्भागवद गीता' और 'कौशुर रामायण' का उर्दू संस्करण स्कूल–कॉलेजों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखने का आदेश दिया है?
a- बिहार सरकार b- पंजाब सरकार
c- कर्नाटक सरकार
d- जम्मू–कश्मीर सरकार

8. कैमरून के पॉल बिया ने 71.3 प्रतिशत मतदान के साथ कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है?
a- 7वीं b- 8वीं
c- 9वीं d- 10वीं

9. किस देश के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 23 अक्टूबर 2018 को चीन और मकाओ को हॉन्ग–कॉन्ग से जोड़ने वाले समुद्र पर बने दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया?
a- नेपाल b- चीन
c- जापान d- रूस

10. सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा?
a- सबरीमाला मंदिर b-अयोध्या मंदिर
c- वैष्णो देवी मंदिर d- राजारानी मंदिर

11. रेलवे ने अपने सफाई कर्मचारियों के पद 'सफाईवाला' का नाम बदलकर क्या नाम रखा है?
a- हाउसकीपिंग वाला
b- हाउसकीपिंग सहायक
c- सफाई सहायक
d- हाउसकीपिंग सफाई

12. वित्तीय सेवाएं देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी क्रेडिट सुईस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार, किस देश के शीर्ष 1 प्रतिशत अमीरों के पास देश की आधी से अधिक (51.5 प्रतिशत) संपत्ति है?
a- नेपाल b- पाकिस्तान
c- बांग्लादेश d- भारत

उत्तरः

1.d- ओसामू शिमोमुरा
विवरणः जापान के वैज्ञानिक तथा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता ओसामू शिमोमुरा का 22 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया । वे 90 वर्ष के थे ।

2.b- ताई जू यिंग
विवरणः भारत की महिला शटलर साइना नेहवाल ने 21 अक्टूबर को डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता । उन्हें विश्व की नंबर–1 ताईवान की ताई जू यिंग के हाथों 13–21, 21–13, 6–21 से हार मिली ।

3.d- जापान
विवरणः जापान की एक कंपनी ने हफ्ते में कम–से–कम 5 दिन 6–6 घंटे की नींद रात के वक्त लेने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया है ।

4 b- असम
विवरणः असम में 46 संगठनों ने केंद्र सरकार के नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के खिलाफ राज्यव्यापी 12 घंटे का बंद बुलाया ।

5.c- बजरंग पूनिया
विवरणः भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने 22 अक्टूबर 2018 को विश्व कुश्ती चौंपियनशिप में रजत पदक जीता । वे विश्व कुश्ती चौंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने ।

6.b- हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली
विवरणः पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली–स्वस्थ दिवाली' अभियान का शुभारंभ किया है ताकि इस दौरान होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके ।

7.d- जम्मू–कश्मीर सरकार
विवरणः जम्मू–कश्मीर सरकार ने सर्वानंद प्रेमी द्वारा लिखित 'श्रीमद्भागवद गीता' और 'कौशुर रामायण' का उर्दू संस्करण स्कूल–कॉलेजों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखने का आदेश दिया है ।

8.a- 7वीं
विवरणः कैमरून के पॉल बिया ने 71.3 प्रतिशत मतदान के साथ 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है । वर्ष 1982 में पहली बार राष्ट्रपति बने पॉल बिया दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से हैं।

9.b- चीन
विवरणः चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 23 अक्टूबर 2018 को चीन और मकाओ को हॉन्ग–कॉन्ग से जोड़ने वाले समुद्र पर बने दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया । ये पुल 55 किलोमीटर लंबा है ।

10. a- सबरीमाला मंदिर
विवरणः सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि आदेश के खिलाफ कोर्ट में 19 पुनर्विचार याचिका दायर की गई हैं ।

11.b- हाउसकीपिंग सहायक
विवरणः रेलवे ने अपने सफाई कर्मचारियों के पद 'सफाईवाला' का नाम बदलकर 'हाउसकीपिंग सहायक' कर दिया है। हालांकि 'सफाईवाला' रेलवे का 'ग्रुप डी' कर्मचारी होता है और ये कर्मचारी चिकित्सा, संचालन व अन्य विभागों में तैनात होते हैं ।

12.d- भारत
विवरणः वित्तीय सेवाएं देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी क्रेडिट सुईस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत के शीर्ष 1 प्रतिशत अमीरों के पास देश की आधी से अधिक (51.5 प्रतिशत) संपत्ति है ।

पाठकों से अपील

प्रिय पाठक वर्ग

पाक्षिक विकासात्मक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' का आठवां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । आशा करता हूं कि पिछला अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। द रीव टाइम्स लोगों को जीवन में प्रगतिशील बनने में कारगर सिद्ध हो, इसी उद्देश्य से आप की प्रतिक्रियाओं, आलोचनाओं, सुझावों तथा परामर्श को सादर आमंत्रित करते हैं ताकि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबन्धि सभी पहलुओं का क्रमबद्ध समावेश किया जा सके ।

आनन्द नायर प्रबन्ध संपादक

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) क्या है?

द रीव टाइम्स

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) साँझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नये और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है । इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ एक पायलट कार्यक्रम के रूप में की गई थी ताकि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता मिल सके और पर्यावरणीय स्थिरता विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 1992 रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से स्थायी, अलग संस्थान बन गया था । इसे स्वतंत्र रूप से एक वित्तीय संगठन के रूप में संचालित किया जाता है जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी), पारा, टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ शहरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है ।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के कामकाज की शैली

1. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों सहित दुनिया भर में सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए दुनिया भर में काम कर रहे 18 एजेंसियों के साथ इसकी अनूठी साझेदारी है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने वाले 183 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र की वैश्विक भागीदारी है ।

2. यह पात्र देशों को पांच मुख्य क्षेत्रों में अनुदान देता है: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अवक्रमण, अंतरराष्ट्रीय जल, रशयन एवं कचरा । यह जैविक विविधता पर सम्मलेन (सीबीडी), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट ढांचा सम्मलेन (युएनएफसीसीसी), स्थायी जैविक प्रदूषको पर स्टॉकहोल्म सम्मलेन (पीओपीएस), बंजर से मुकाबला के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (यूएनसीसीडी), मरकरी के विषय में मिनामाटा सम्मलेन के लिए वित्तपोषक के रूप में भी काम करता है तथा ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थो पर मोंट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में भी मदद करता है।

3. यह बहु–हितधारक गठजोड़ों के समर्थन के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने, हरित नगर निर्माण, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और समृद्ध तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नवप्रवर्तनक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

विश्व के दस अतुलनीय पुस्तकालय

द रीव टाइम्स

पुस्तकालय ज्ञान और कल्पना के माध्यम से मानव जाति के लिए अविश्वसनीय उपहार हैं, जो प्रेरणा प्रदान करते हैं और कठिन कामों को करने में सहायता प्रदान करते हैं। कभी–कभी यह ज्ञान के शक्तिगृह (power house) के रूप में काम करता है, क्योंकि इस तक पहुंचने के बाद मनुष्य की कल्पना शक्ति में बढ़ोतरी होती है। यहां, हम दुनिया भर में फैले 10 अविश्वसनीय पुस्तकालयों और किताबों की दुकान की सूची दे रहे हैं।

विश्व के दस अतुलनीय पुस्तकालय और पुस्तक भवन

1. अल-कारवायिन पुस्तकालय

स्थान: फेज, मोरक्को

संस्थापक: इसकी स्थापना फातिमा एल–फिहरिया ने 859 ईस्वी में उस समय की थी, जब बीजगणित का अविष्कार हुआ था ।

पुस्तकें: यहाँ 4,000 दुर्लभ पुस्तकें और प्राचीन अरबी विद्वानों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियां मौजूद हैं।

विशेषता: यह महिला द्वारा स्थापित दुनिया की पहली पुस्तकालय है, जो नौवीं शताब्दी के कुरान सहित प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों के अनूठे संग्रह के लिए प्रसिद्ध है।

2. सेंट गैलेन की अभय लाइब्रेरी

स्थान: स्विट्जरलैंड

संस्थापक: सेंट ओथमर ने 8वी शताब्दी में इसकी स्थापना की थी ।

पुस्तकें: यहाँ 8 वीं सदी तक लिखे गए पुस्तकों/पांडुलिपियों के 160,000 संस्करण संग्रहित हैं ।

विशेषता: यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण मठ पुस्तकालयों में से एक है।

3. फ्रांस की राष्ट्रीय पुस्तकालय

स्थान: पेरिस, फ्रांस

स्थापना : 1461 ईस्वी

पुस्तकें: यहाँ 14 लाख से ज्यादा पुस्तकों का संग्रह है ।

विशेषता: यह पुस्तकालय परिपक्व वनक्षेत्र में 4 खुली किताब आकार वाले टॉवर के रूप में व्यवस्थित हैं।

4. सेंट कैथरीन मठ

स्थान: साउथ सिनाई, मिस्री

संस्थापक: यह दुनिया का सबसे पुराना ईसाई मठों की पुस्तकालय है जिसे 548–565 ईस्वी के बीच बनाया गया था।

पुस्तकें: इसमें 3,000 धार्मिक और शैक्षणिक पांडुलिपियों और होमर और प्लेटो के पहले संस्करणों सहित लगभग 8,000 मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं।

विशेषता: यह उस स्थान पर बनाया गया था, जहां पैगंबर मूसा ने माउंट सिनाई (बाइबिल में वर्णित माउंट होरेब, जिसे स्थानीय रूप से जैबेल मुसा के रूप में जाना जाता है) पर चढ़ते समय बर्निंग बुश के चमत्कार के दौरान परमेश्वर के साथ बातचीत के क्रम में प्रवर्तन के दस आदेशों को प्राप्त किया था।

5. रॉयल ग्रामर स्कूल जंजीर पुस्तकालय

स्थान: गिल्डफोर्ड, इंग्लैंड

संस्थापक: लगभग 18 वीं शताब्दी के मध्य युग में

पुस्तकें: यहाँ 1600 लाख से भी ज्यादा पुस्तकों का संग्रह है ।

विशेषता: यह पुनर्जागरण के युग के दौरान स्थापित किया गया था जब विद्वानों और लाइब्रेरियन जनता के साथ ज्ञान साझा करना चाहते थे, लेकिन जनता पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए जंजीर पुस्तकालय की अवधारणा का जन्म हुआ जो आज भी अस्तित्व में है जैसे रॉयल ग्रामर स्कूल जंजीर पुस्तकालय ऑफ गिल्डफोर्ड, इंग्लैंड जहां सभी पुस्तकों और संधिपत्रों को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है।

6. एडमॉन्टन एब्बी लाइब्रेरी

स्थान: ऑस्ट्रिया

संस्थापक: इसकी स्थापना 1074 ईस्वी में साल्जबर्ग के आर्कबिशप गेभार्ड ने की थी ।

पुस्तकें: इसमें 1,400 पांडुलिपियों और 900 इन्जिनुबुले (incunabulae) हैं।

विशेषता: यह दुनिया में सबसे बड़ा मठ पुस्तकालय है और यह बेजोड़ वास्तुकला, कला, और पांडुलिपियों के लिए जाना जाता है।

दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की सूची

7. वास्कॉनसेलस लाइब्रेरी

स्थान: मेक्सिको

संस्थापक: इसका डिजाइन अल्बर्टो कलच ने अंतर्राष्ट्रीय वास्तुशिल्प प्रतियोगिता जीतने के बाद किया था और इसका उद्घाटन 6 मई, 2006 को हुआ था ।

पुस्तकें: यहाँ 50,000 लाख पुस्तकों के साथ–साथ वास्तुकला के विशेष संग्रह हैं ।

विशेषता: इसे मेगाबीबिलीओटेका के रूप में जाना जाता है जिसके कारण इसकी विशाल संरचना 4,09,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है। इस पुस्तकालय को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि पूरा पुस्तकालय मैट्रिक्स के सपने जैसा दिखता है, क्योंकि क्रिस्टल अलमारियों के कारण सभी पुस्तक हवा में तैरते नजर आते हैं।

8. म्युनिसिपल लॉ लाइब्रेरी

स्थान: म्युनिक, जर्मनी

संस्थापक: इसकी स्थापना जॉर्ज वॉन हौबेरिस्सेर ने 1867–1908 ईस्वी के बीच किया था ।

पुस्तकें: कानून से संबंधित प्रत्येक ग्रंथ के साथ–साथ यहाँ 17,500 पुस्तकों का संग्रह है।

विशेषता: यह सबसे सुंदर पुस्तकालयों में से एक है और दुनिया में गॉथिक रिवाइवल वास्तुकला शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि यह साहित्य के जादू का आनंद लेने के लिए एक उज्ज्वल और गर्म जंगल जैसा दिखता है।

9. एप्पोस शिप लाइब्रेरी

स्थान: होर्दालंद, सोगं ओग फ्जोर्दाने एंड मेरे ओग रोम्स्दल इन नॉर्वे

संस्थापक:1963 ईस्वी

पुस्तकें: यहाँ 6000 से भी ज्यादा पुस्तकों का संग्रह है ।

विशेषता: यह दुनिया की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी है जिसमें कप्तान, तीन लाइब्रेरियन और एक कलाकार शामिल है जिसे तीन देशों के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

10. नेशनल लाइब्रेरी, चेक गणराज्य

स्थान: चेक गणराज्य

स्थापना: 1722 ईस्वी में किलियन इग्नत्ज डिएन्त्जेन्होफेर ने इसे स्थापित किया था ।

पुस्तकें: यहाँ 6,919,075 पुस्तकें, 21,204 पांडुलिपियों और 4,200 इनुनाबुला संग्रहित हैं।

हिमाचल प्रदेश की रियासतें और उनके संस्थापक

यहां जानेगें हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख रियासतों के बारे में, उनकी स्थापना किसने की और कब की

रियासत	संस्थापक	स्थापना वर्ष
सुजानपुर	घमंड चंद	
नूरपुर	जेतपाल	1000 ई0
सुकेत	वीर सेन	1200 ई0
बलसन	अलोक सिंह	1200 ई0
भज्जी	चारू राजा	
दरकोटी	दुर्गा सिंह	
कुम्हारसेन	किरत चंद	1100 ई0
देलथ	पृथ्वी सिंह	

रियासत	संस्थापक	स्थापना वर्ष
ठियोग	जयचंद	1667 ई0
जुब्बल	कर्णचंद	
क्योंथल	गिरी	765 ई0
रतेश	राम सिंह	
सिरमौर	सुभंश प्रकाश	1195 ई0
कुनिहार	अभोज देव	1154 ई0
महलोग	बीर चंद	1170 ई0
डाडा सिब्बा	सिवर्ण चंद	1550 ई0

रियासत	संस्थापक	स्थापना वर्ष
मंडी	बाहू सेन	1200 ई0
कहलूर	वीर चंद चंदेल	900 ई0
गुलेर	हरी चंद	1405 ई0
सिब्बा	शिवराम	4500 ई0
नालागढ़	अजय चंद	1000 ई0
कहलूर	वीर चंद चंदेल	900 ई0
चंबा	मेरु वर्मन	550 ई0
जसवां	पूर्ण चंद	1170 ई0

भारतीय रक्षा क्षेत्र पर सामान्य ज्ञान क्विज

द रीव टाइम्स

भारतीय रक्षा क्षेत्र पर तैयार की गयी क्विज का उद्देश्य भारतीय रक्षा क्षेत्र पर से सम्बंधित आवश्यक जानकारी को प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि प्रतियोगी छात्र उनके अभ्यास के द्वारा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्वरुप से परिचित हो सकें । साथ ही साथ उनमें भारतीय रक्षा क्षेत्र की व्यापक समझ भी विकसित हो सके।

1. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ..... में स्थित है।
अ. श्रीहरिकोटा ठ. बंगलुरू ब. महेंद्रगिरि
क. अहमदाबाद
उत्तर – अ

2. डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
अ. नई दिल्ली ठ. ओडिशा ब. कर्नाटक
क. महाराष्ट्र
उत्तर – अ

3. निम्न में से किस देश के पास क्रायोजेनिक इंजन से संबन्धित तकनीक नहीं है?
अ. रूस ठ. जापान ब. चीन
क. कनाडा
उत्तर – क

4. भारत में मुख्य नियंत्रण सुविधा (MCF) कहाँ स्थित है?
अ. हासन (कर्नाटक) ठ. भोपाल (मध्य प्रदेश)
ब. चाँदीपुर (ओडिशा) क. भोपाल और हासन दोनों जगह
उत्तर – क

5. निम्न में से कौन सी मिसाइल 'फायर एंड फॉरगेट' के सिद्धांत पर काम करती है?
अ. ब्रह्मोस ठ. आकाश ब. नाग
क. शौर्य
उत्तर – ब

6. 'ध्रुव' क्या है?
अ. टेंक ठ. उन्नत एवं हल्का हेलीकाप्टर
ब. एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली
क. मिसाइल
उत्तर – ठ

7. निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है?
अ. ईरान ठ. अफगानिस्तान
ब. पाकिस्तान क. भारत
उत्तर – क

8. भारत किस देश से अधिकतम रक्षा उपकरणों की खरीद करता है?
अ. कनाडा ठ. संयुक्त राज्य अमेरिका
ब. इजरायल क. चीन
उत्तर –ठ

9. मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
अ. विशाखापत्तनम ठ. कोलकाता
ब. मुंबई क. कांडला
उत्तर – ब

10. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ..... में स्थित है?
अ. कर्नाटक ठ. महाराष्ट्र
ब. उत्तराखंड क. दिल्ली
उत्तर – ठ

सामाजिक सुरक्षा : ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चुनौती

आईआईआरडी का सर्वेक्षण दिखाता है गांव की असल तस्वीर

विकास की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छूट गया है। ऐसा लगता है कि अब 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होने से कोई रोक नहीं सकता है। हम ज्ञान से विज्ञान तक के क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाढ़ रहे हैं और दुनिया हमारे देश को सलाम कर रही है। पर क्या इस विकास का मूल और आधार इसके गांव और ग्रामीण भी इसी विकास की गति के साथ इस दौड़ में अग्रसर है, इसमें संदेह है । ऐसा नहीं कि सन् संतालीस के बाद विकास हुआ नहीं या कम हुआ है किंतु विकास के मायने गांव में आकर बदल जाते हैं। रोजमर्रा की ज़िंदगी आसान हुई है किंतु सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और दिल्ली के विकास का हज़ारों मील दूर गांव में हूबहू पहुंचना.....संभव नहीं हो पाया। कुछ समय पहले आईआईआरडी द्वारा शिमला ज़िले के दूरदराज गांव शोली में एक महत्वपूर्ण विस्तृत सर्वेक्षण करवाया गया। इस सर्वेक्षण में अनेक मानकों पर गांव की वास्तविक स्थिति का आकलन जब हुआ तो ये विकास की दौड़ वहां धीमी पड़ती ही नज़र आई। टीन–टप्पर, कंकरीट का जंगल ही विकास नहीं होता, विकास हमारी सामाजिक सुरक्षा, ज्ञान, शिक्षा के अलावा अपने कौशल विकास का भी आधार होता है। संस्था ने इस सर्वेक्षण को प्रत्येक मानकों पर बारीकि से करवाया तथा इसमें प्राप्त आंकड़ों से कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई।

सर्वेक्षण क्षेत्र : शिमला ज़िले के ननखड़ी विकास खण्ड का गांव शोली

कुल परिवार / कुटुम्ब , कुल आबादी : 2233

महिला: 1085	पुरुष : 1148	सामान्य श्रेणी : 1384	अनु0 :815,	ओबीसी : 34

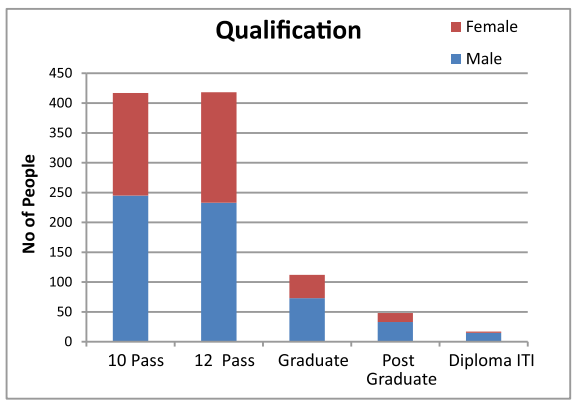

शिक्षा :

- दसवीं पास लोगों की संख्या : 417, 12वीं पास लोगों की संख्या : 418
- स्नातक : 112, स्नातकोत्तर :48, आईटीआई प्रशिक्षित : 17

492 परिवारों में मकानों की स्थिति

- पक्के मकान : 59, सेमी पक्के मकान : 60, कच्चे मकान : 373

रोजगार

- सरकारी नौकरी :99, निजी व्यवसाय :81
- कृषि / बागवानी आधारित

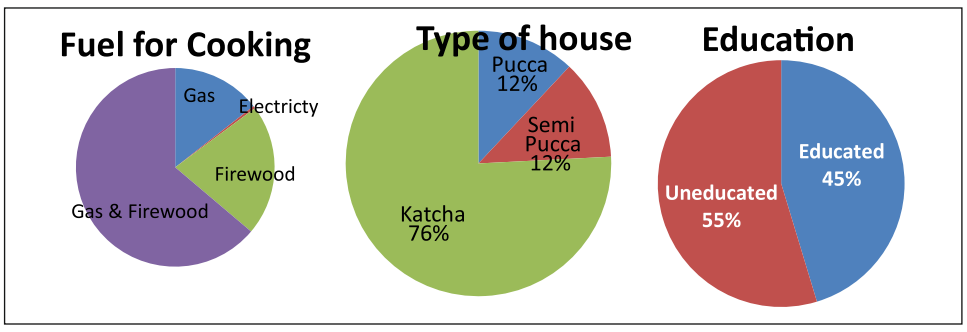

- **व्यवसाय :416**
- स्वरोजगार :75

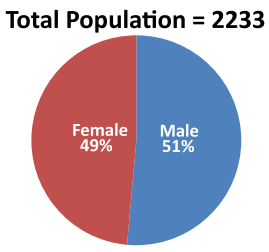

सामाजिक सुरक्षा :

- जीवन बीमा पॉलिसी धारक : 174 / 2233 , वाहन बीमा धारक : 36

घर से कूड़ा निदान

- सामुदायिक अपशिष्ट कूड़े को फैंकना : 12
- निजी डंप में कूड़ा : 35, पिट में कूड़ा जलाना : 140
- कूड़ा दबाना : 252, कूड़े को सड़क किनारे फैंकना : 53

राष्ट्रीय अभियान भी गांव में गति नहीं पकड़ पाते हैं, इसका सर्वेक्षण में खुले तौर पर प्राकट्य हुआ है। स्वच्छता अभियान 10–15 वर्षों से आज एक मिशन बन चुका है। किंतु गांव में इसे लोग आज भी अपने–अपने हिसाब से डंप करते हैं। कोई सड़क पर फैंक रहा तो कोई कहीं भी अपने हिसाब से इसका निदान कर रहा है।

सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता

सबसे चौकानें वाले आंकड़े तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर सामने आए हैं। इस जीवन की निश्चितता सदैव संदेह और अंधेरे में रही है । किसी को पता नहीं कि अगला पल क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती स्वयं के साथ–साथ परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की भी रहती है। देश की बड़ी–बड़ी सरकारी एवं निजि कंपनियां स्वयं को जन हितैषी बताकर हर व्यक्ति और घर को सुरक्षा घेरे में लाने के दावे करती आ रही हैं । लेकिन हिमाचल के इस गांव में हुए सर्वेक्षण में जो आंकड़े सामने आऐं हैं वो तो सारी पोल खोल कर रख रहे हैं । कुल 2233 आबादी वाला गांव मात्र 174 लोगों की जीवन बीमा के साथ सामाजिक सुरक्षा को लेकर अपने विकास को दिखा रहा है। 2233 की आबादी और कुल 492 परिवार और कुल 174 लोग स्वयं के भविष्य को सुरक्षित करने के प्रति जागरुक.....ये तथ्य एक हैरत में डालने वाला लगता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इतनी बड़ी आबादी और परिवार वाले गांव में किसी के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए अथवा घर के मुखिया को किसी दुर्घटना में जान गंवानी पड़े तो पीछे छूटेगा अकेला, बिलखता और अंधेरे में डूबा परिवार। स्थितियां तो यहां तक बद्तर हो जाती है कि दुर्घटना के बाद अंतिम यात्रा हेतु भी कई बार बचत नहीं होती है। ऐसे में यदि कोई सामाजिक सुरक्षा का साधन हो तो देर–सवेर एक निश्चिंतता रहती ही है। विशेष रुप से जब हम हिमाचल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ज़िला शिमला अपने आप में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जटिलताऐं लिए हुए हैं। यहां का जीना पहाड़ों की कठिन पगडंडियों से होकर गुजरता है। ऐसे में दुर्घटना या अनहोनी कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सर्वेक्षण में कुल 174 लोगों ने ही माना कि उनकी कोई बीमा पॉलिसी है। इसके अलावा इतनी बड़ी आबादी इससे वंचित है। कई लोगों को तो पता भी नहीं कि जीवन बीमा है क्या?

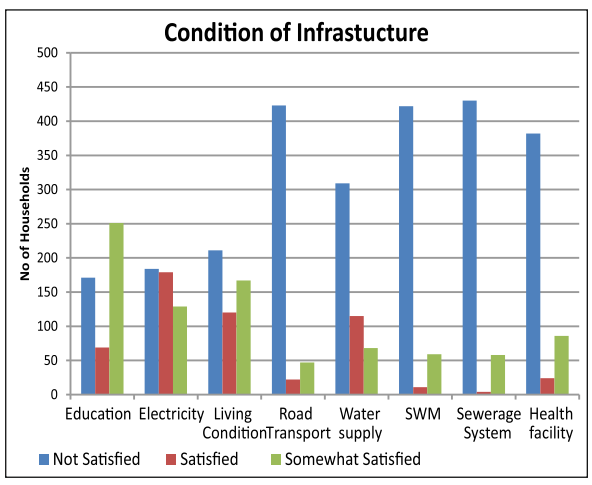

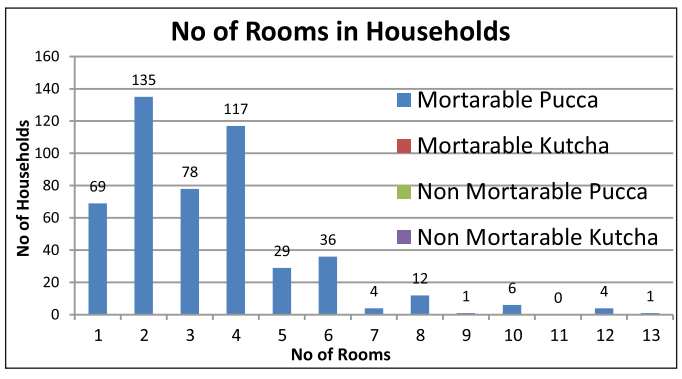

अभी एक पूर्व में ही द रीव टाइम्स के एक अंक में प्रधान संपादक डॉ0 एल सी शर्मा ने शोली गांव के आस–पास के क्षेत्र के दो उदाहरण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा की पोल खोली थी। दो परिवारों को किस प्रकार विपदा ने घेरा जब उनके घरों के मुखिया को नियति ने एक दुर्घटना में छीन लिया। उनके अंतिम संस्कार तक के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। चिंता ये कि अब बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और भविष्य की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया। यह तभी हुआ क्योंकि उन दोनों घरों के मुखिया और परिवार का कोई भी जीवन बीमा नहीं था। यदि होता तो भविष्य के लिए कुछ राहत मिलती साथ ही इस संकट के समय में आर्थिक सहायता व भरोसा भी।

उत्तरदायित्व :

इस दौर में भी यदि सामाजिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित नहीं करवा पर रहे हैं तो इसे हमारी व्यवस्था और लाचारी की विडम्बना कहा जाऐगा। आवश्यकता है लोगों को जागरुक करने और अधिक से अधिक जोड़ने की ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस सामाजिक सुरक्षा के घेरे में लाया जा सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित दिशा की ओर ले जाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा सके। इसके लिए भारत सरकार की वर्तमान सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख बिंदुओं को समझना आवश्यक है। आज तो बैक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बचत खाता खुलने के साथ ही वार्षिक 12 रुपये यानि मासिक 1 रुपये में 2 लाख तक का बीमा किया जा रहा है। यानि इस बीच कोई दुर्घटना हो जाए तथा जीवन न बच पाया तो कम से कम 2 लाख तक की फौरी राहत उस परिवार को प्राप्त होगी।

सर्वेक्षण में संस्था की इस रिपोर्ट के बाद संस्था ने इस क्षेत्र में सराहनीय पहल भी की है तथा ग्रामीणों को जागरुक करने के लिए एक बड़े एवं व्यापक स्तर पर शोली गांव में संसाधनों की उपलब्धता एवं जागरुकता कार्यक्रमों हेतु प्रयास किए हैं। गांव को सोलर लाईट से गुलजार किया गया है तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी की गई है। इस सर्वे के बाद लोग स्वयं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए गांव में निरंतर कार्यक्रम और आयोजन किए जाते हैं जिसमें रुरल कनक्लेव भी शामिल है।

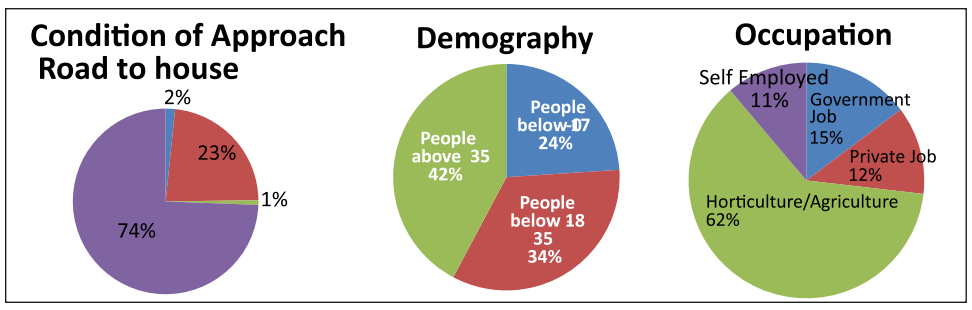

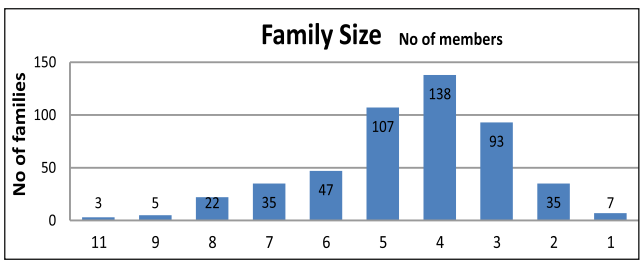

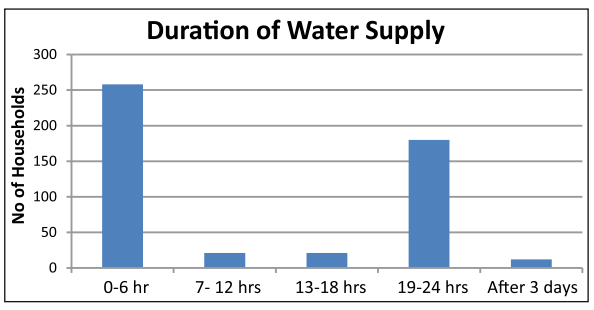

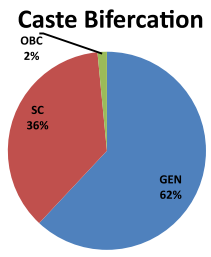

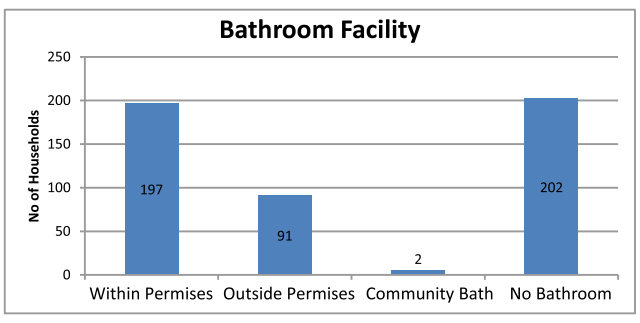

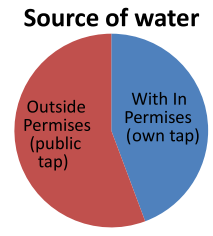

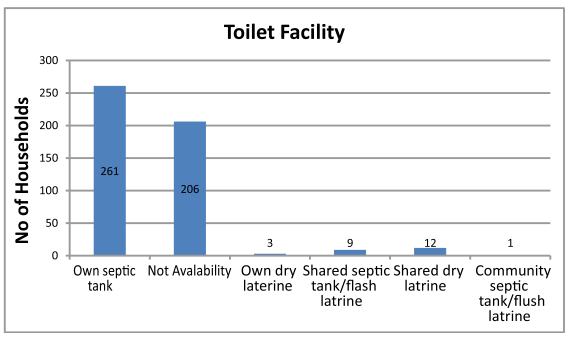

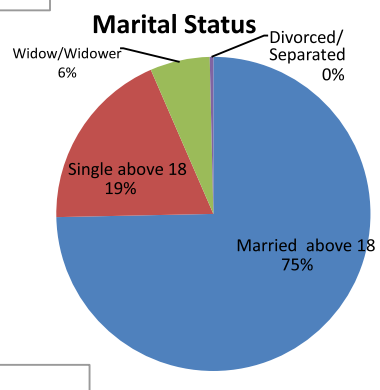

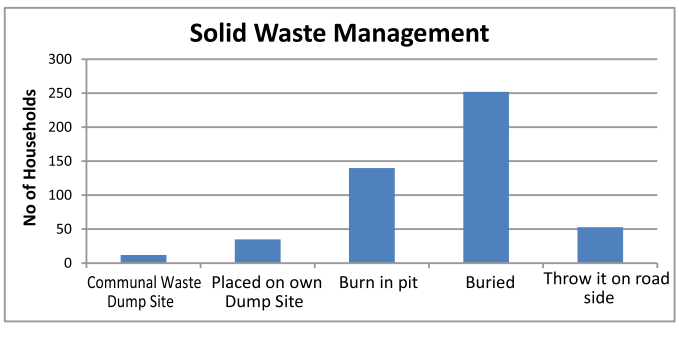

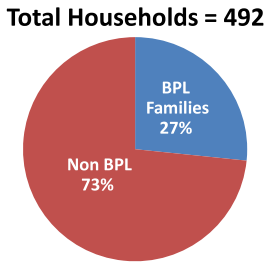

'सुकन्या समृद्धि योजना'

केंद्र की मोदी सरकार ने 4 दिसंबर 2014 को बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत की। सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है। हाल ही में किए गए बदलाव के तहत अब इस योजना में न्यूनतम जमा राशि को 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। इसमें बालिका के माता–पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के कई प्रमुख हैं बिंदु हैं जिसके बारे में द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं।

सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता–पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग–अलग एक खाता खोल सकते हैं। यदि जुड़वा बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को मोदी सरकार की तरफ से मिला बड़ा तोहफा

खाता खोलने के लिए जरूरी राशि

सुकन्या समृद्धि का एक खाता 1000 रुपए में शुरुआती जमा राशि पर खोला जा सकता है। इससे पहले इस खाते में प्रति वर्ष 1000 रुपए न्यूनतम जमा राशि जमा करनी होती थी जो अब सिर्फ 250 रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकेगा। यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा।

खाता संचालन बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता–पिता खाते को संचालित कर सकते हैं इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है।

इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

जमा राशि निकालने की शर्तें

बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।

खाता कब होगा मेच्योर

बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर ही खाता मेच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है।

आयकर में छूट का लाभ

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80–जी के तहत छूट दी जाएगी।

अनियमित भुगतान पर जुर्माना

अनियमित भुगतान अगर खाते में अनियमित भुगतान किया जाता है तो प्रति वर्ष कम से कम 50 रुपए का जुर्माना निर्धारित राशि के साथ लिया जाएगा। विड्रॉल (पैसा निकालना) 50 प्रतिशत राशि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 18 वर्ष की आयु होने के बाद उच्च शिक्षा और शादी की के लिए इस्तेमाल होगी।

पीपीएफ से ज्यादा ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश राशि पर ही पहले टैक्स छूट थी लेकिन इस बजट में इसके ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट दी गई है। इस मामले में यह PPF के बराबर हो गया जिस पर तीन स्तरों पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ब्याज के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना PPF से ज्यादा आकर्षक है। PPF पर 8 फीसदी ब्याज मिल रही है जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5 फीसदी ब्याज है।

ऐसे खुलवाएं खाता

आप दो तरह से सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाने के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला– कि आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और वहां शाखा

प्रबंधक से इस विषय में जानकारी मांगे। शाखा प्रबंधक आपको इस योजना के विषय में हर बात बताएंगे। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करें।

पोस्ट ऑफिस में ऐसे खोले खाता

अपने निकटतम पोस्टऑफिस में जायें और वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म प्राप्त करें। अगर समय नहीं है, तो आप इंटरनेट से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बेटी की फोटोग्राफ लगाकर व फॉर्म भर कर उसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिये। फॉर्म भरें और उसमें सही – सही हस्ताक्षर करें अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी संलग्न करें अगर आधार कार्ड है, तो उसकी कॉपी संलग्न करना ज्यादा बेहतर होगा। बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी, अपनी और अपनी बेटी की दो–दो पासपोर्ट साइज फोटो। अकाउंट या खाता खुलने के बाद आप पैसे चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं।

अधिकतम तीन खाते

एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम दो से तीन खाते खोले जा सकते हैं। इस योजना में दो ही खाते का प्रावधान है लेकिन अगर जुड़वा लड़की है तो इस संबंध में आपको प्रमाण पत्र पेश करना होगा जिसके बाद आप तीसरा खाता खुलवा सकते हैं। किसी भी दशा में 3 से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है। खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपए या अधिकतम राशि 1,50,000 वार्षिक जमा की जा सकती है।

योजना की ब्याज दर घटाए

इस खाते की कुल अवधि 21 साल है और इस खाते पर ब्याज 8.40 प्रतिशत का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं से 0.1 फीसदी ब्याज की कटौती की थी जिसके बाद इन खातों पर भी मिलने वाला ब्याज कम हो गया है। इस योजना के तहत मिलने वाला ब्याज परिवर्तनीय होता है। योजना में आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (सी) के अंतर्गत टैक्स की छूट दी जाती है।

'बेटी है अनमोल योजना'

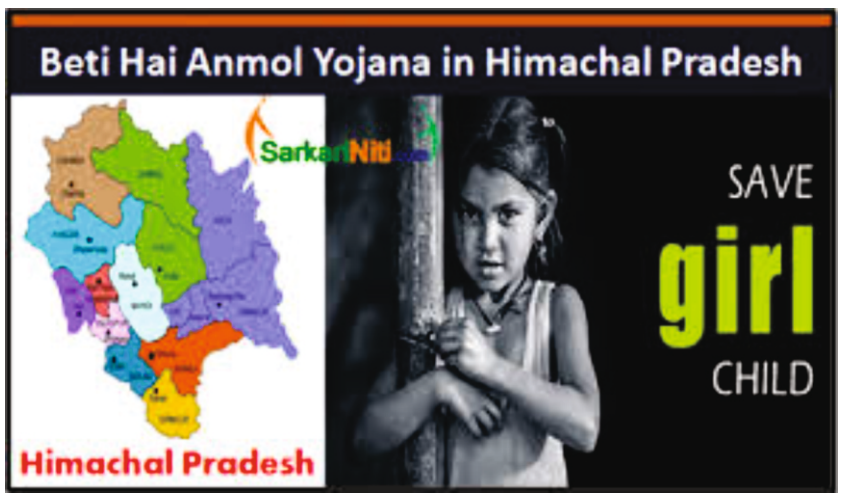

"बेटी हैं अनमोल योजना" हिमाचल प्रदेश की यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हैं। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवारों की लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से स्नातक स्तर पर समकक्ष पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को 5000 हजार रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

"बेटी हैं अनमोल योजना" के अंतर्गत बीपीएल परिवारों से संबंधित लड़कियों को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता और राज्य में बालिका के जन्म के समय और फिर वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में भी सहायता प्रदान की जाती है।

"बेटी हैं अनमोल योजना" का मुख्य उद्देश्य लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 01– 12 वीं कक्षा में पढ़ रही लड़कियों को सरकार 300 से 1200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों की लड़कियों को स्नातक स्तर या समकक्ष कोर्स कर रही बीपीएल परिवार की लड़कियों को सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए 5000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। जो छात्रायें बीए, बीटेक, कॉमर्स, एमबीबीएस,एलएलबी तथा बीएड की पढ़ाई करने वाली छात्रायें है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

बेटी हैं अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ

हिमाचल प्रदेश में बेटी हैं अनमोल योजना से छात्राओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। जिनके बारे में नीचे विवरण दिया गया हैं। "बेटी हैं अनमोल योजना" हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए है, इस योजना का लाभ परिवार की दो लड़कियों के लिए है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोस्ट ऑफिस /बैंक खाते में 12,000 रूपये प्रति लड़की के खाते में जमा किए जायेंगे।

बेटी हैं अनमोल योजना के तहत छात्रवृत्ति 300 से 1200 रूपये पहली क्लास से 12 वीं कक्षा तक लड़कियों को उनकी पुस्तकों /कपड़े आदि के लिए दिया जायेगे।

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और स्नातक स्तर में पढ रही लड़कियों को 5000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

बेटी हैं अनमोल योजना के अंतर्गत 05 जुलाई 2010 के बाद पैदा हुई सभी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।

बेटी हैं अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लाभ लेने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं।

आधार कार्ड की फोटो कॉपी
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
बीपीएल राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र

बेटी हैं अनमोल योजना ऑनलाइन आवेदन

- यदि आप "बेटी हैं अनमोल योजना" हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद "ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश" का होम पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद होमपेज पर वेबपेज के दाईं ओर "लॉगिन" अनुभाग के नीचे "नया पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें।
- उसके बाद अगले पेज पर एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद "रजिस्टर बटन" पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदक व्यक्ति आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक व्यक्ति को होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर बाईं ओर "सेवा की सूची" अनुभाग पर क्लिक करें।
- इसके बाद सेवाओं की सूची में "महिला और बाल कल्याण विभाग" अनुभाग के अंतर्गत "बेटी है अनमोल योजना" के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अगले पेज पर "यूजर आईडी" और "पासवर्ड" का प्रयोग करके अगला लॉगिन करें और "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। इस आवेदन पत्र में आवेदक को माता का विवरण, लड़की बाल विवरण, पता विवरण, बैंक विवरण भरना होगा और नीचे दिए गए समर्थन दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "सबमिट करें बटन " पर क्लिक करना होगा और अब आप पुष्टि की रसीद का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

बेटी हैं अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में ऑफलाइन आवेदन

हिमाचल प्रदेश में आवेदक व्यक्ति "बेटी हैं अनमोल योजना" के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आवेदककर्ता व्यक्ति को संबंधित ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी संबंधित आवेदन के लिए संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी को मंजूरी के लिए भेज देंगे। बेटी हैं अनमोल योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

(edistrict.hp.gov.in)

Advertorial

प्रदेश में मिशन रीव स्थापित करेगा सलाहकार बोर्ड

ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक बनेंगी सलाहकार समितियां

मिशन रीव और आमजन के मध्य सलाहकार बोर्ड करेगा सेतु का कार्य

इच्छुक समाजसेवियों, संस्थाओं/संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं जागरूक नागरिकों से सलाहकार बोर्ड की सदस्यता हेतु सुझाव आमंत्रित है

आजीवन सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर सलाहकार बोर्ड में मान्यता दी जाएगी

मिशन रीव सचिवालय

संवाहक बनें

अपना गांव-अपना धन, अपना विकास
अपना बैंक अपना लोन...
आओ बदलें गांव की तस्वीर...
संवाहक बनें अपने गांव अपने समाज के

निधि कंपनी (बैंकिंग)

ग्रामीण सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देकर स्वसंचित धन को व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास हेतु ऋण प्रदान करना (सभी सलाहकार समितियों में लागू)

पंचायत स्तर | **खण्ड स्तर** | **ज़िला स्तर** | **राज्य स्तर**

रीव पंचायत सलाहकार बोर्ड

11 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड
(प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्य, बुद्धिजीवि, समाजसेवी एवं अन्य इच्छुक) बैठक प्रतिमाह

पंचायत स्तर सलाहकार बोर्ड के कार्य

- मिशन रीव की वर्तमान ग्रामीण सेवाओं एवं क्रियान्वयन की समीक्षा
- मिशन रीव के अंतर्गत नवीन सुझावों, सेवाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना
- मिशन रीव के अंतर्गत गठित निधि कंपनी (बैंक) के लिए ग्रामीणों में बचत की आदत को बढ़ावा देना तथा संचित निधि की 70 प्रतिशत राशि का ऋण के रुप में वितरित करने हेतु अनुशंसा करना

रीव खण्ड स्तरीय सलाहकार बोर्ड

25 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड
(ग्राम पंचायत प्रधान, एनजीओ प्रतिनिधि समाजसेवी एवं अन्य इच्छुक) दो माह में एक बैठक

ब्लॉक स्तर पर सलाहकार बोर्ड के कार्य

- मिशन रीव की मौजुदा तथा नयी सेवाओं की दीर्घकालीनता एवं रीव स्वयंसेवियों के उत्थान प्रक्रिया की समीक्षा करना
- मिशन रीव के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सेवाओं का चयन तथा कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना
- मिशन रीव के अंतर्गत गठित निधि कंपनी बैंक के लिए ग्रामीणों को संचित निधि की 20 प्रतिशत राशि का ऋण के रुप में वितरित करने हेतु अनुशंसा करना

रीव ज़िला स्तरीय सलाहकार बोर्ड

35 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड
(चेयरमैन पंचायत समिति, एनजीओ प्रतिनिधि समाजसेवी एवं अन्य इच्छुक) तीन माह में एक बैठक

ज़िला स्तर पर सलाहकार बोर्ड के कार्य

- मिशन रीव के मौजुदा एवं नये विकासात्मक लक्ष्यों (संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी के दृष्टिगत) एवं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा करना
- मिशन रीव के अंतर्गत गठित निधि कंपनी बैंक के लिए ग्रामीणों को संचित निधि की 10 प्रतिशत राशि का ऋण के रुप में वितरित करने हेतु अनुशंसा करना

रीव राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड

45 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड
(चेयरमैन ज़िला परिषद्, एनजीओ प्रतिनिधि समाजसेवी एवं अन्य इच्छुक) वर्ष में दो बैठक

राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड के कार्य

- मिशन रीव की मौजुदा नीतियों की समीक्षा तथा नई नीतियों का निर्माण करना
- मिशन रीव की गतिविधियों एवं सेवाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करना
- मिशन रीव के अंतर्गत गठित निधि कंपनी बैंक के लिए ग्रामीणों को संचित निधि की 5 प्रतिशत राशि का ऋण के रुप में वितरित करने हेतु अनुशंसा करना

यदि आपमें जज़्बा है समाजसेवा, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक बदलाव लाने का तो आज ही जुड़ें मिशन रीव से और बनिए सलाहकार बोर्ड के सदस्य

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें

Mob. 94184 04334 www.missionriev.in/advisory.aspx